Useful For Prelims

Date: 11-11-2025

सम-सामयिक

विज्ञान के क्षेत्र में यूरोप को पछाड़ महाशक्ति बना चीन

जनसत्ता संवाद

अंतरराष्ट्रीय विज्ञान के क्षेत्र में अब चीन काफी आगे निकल चुका है। नए अध्ययन से पता चलता है कि कैसे चीन अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों में अमेरिका से आगे निकल रहा है और अनुसंधान का एजंडा तय कर रहा है। वैश्विक शोध का क्षेत्र अब एक अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। 'प्रोसीडिंग्स आफ द नेशनल एकेडमी आफ साइंसेज' (पीएनएएस) में प्रकाशित सर्वेक्षण के मुताबिक, 2023 तक चीनी वैज्ञानिक अमेरिकी सहयोगियों के साथ किए गए लगभग आधे शोध कार्यों का नेतृत्व कर रहे थे। यह एक ऐतिहासिक आंकड़ा है, जो चीन के तेजी से बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। अब जब भी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्दों की बात आती है, तो चीन अनुसंधान का एजंडा तय करता है।

वास्तविक वैज्ञानिक शक्ति को दिखाने के लिए अब सिर्फ नोबेल पुरस्कारों जैसे पुराने, लेकिन प्रतिष्ठित पैमानों या केवल शोध प्रकाशनों की संख्या जैसे पारंपरिक संकेतक काफी नहीं हैं। चीन की वैज्ञानिक तरक्की और प्रभाव को मापने के लिए अब अन्य नए मानदंडों का उपयोग किया जा रहा है।

लगभग साठ लाख शोध पत्रों के विश्लेषण से पता चलता है कि 2023 में अमेरिका-चीन के संयुक्त अध्ययनों में 45 फीसद में चीनी वैज्ञानिकों ने नेतृत्व किया। वर्ष 2010 में यह आंकड़ा 30 फीसद था। अगर यह रुझान जारी रहता है, तो 2027-28 तक कृत्रिम मेधा, सेमीकंडक्टर से जुड़े शोध और पदार्थ विज्ञान (मटीरियल साइंस) जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में प्रमुख भूमिकाओं में चीन अमेरिका की बराबरी कर लेगा।

वैज्ञानिक प्रकाशनों के मामलों में भी चीन आगे है। नई जी 20 शोध रपट के मुताबिक, लगभग नौ लाख वैज्ञानिक प्रकाशन चीन से प्रकाशित हो रहे हैं। यह 2015 की तुलना में तीन गुनी बढ़ोतरी को दिखाता है। नेचर इंडेक्स, 150 महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं का मूल्यांकन करता है। इसमें चीन ने अमेरिका को काफी पहले ही पीछे छोड़ दिया है। नेचर इंडेक्स जिन दस प्रमुख संस्थानों में प्रकाशनों का मूल्यांकन करता है, उनमें सात चीनी संस्थान हैं।

लगभग 20,000 वैज्ञानिक संस्थान होने के बावजूद, पश्चिमी देशों के लिए यह स्थिति कमजोर नजर आती है। हालांकि, अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अभी भी नेचर रैंकिंग में पहले स्थान पर है, लेकिन दूसरे से लेकर नौवें स्थान तक सिर्फ चीनी विश्वविद्यालय ही काबिज हैं। अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी (एमआइटी) दसवें स्थान पर है।

चीन ने विज्ञान के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। इसे अपनी विकास रणनीति का मुख्य आधार बना दिया है। देश अब अपने शोध कार्य को अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए ज्यादा खोल रहा है और इस साझेदारी को सक्रिय रूप से व्यवस्थित कर रहा है। चीनी छात्रों और वैज्ञानिकों को दुनिया भर में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसी रणनीति के दम पर, वैश्विक सहयोग का एक मजबूत नेटवर्क तैयार हुआ है।

चीन खासकर तकनीकी उद्योगों में भारी निवेश कर रहा है। वह अपनी बुनियादी ढांचा परियोजना, 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (बीआरआइ) का इस्तेमाल शिक्षा के निर्यात के लिए भी कर रहा है। इस रणनीति के तहत, अरबों डालर खर्च कर वैश्विक प्रतिभाओं को चीन आकर्षित कर रहा है और दुनिया भर में संपर्क बनाए जा रहे हैं।

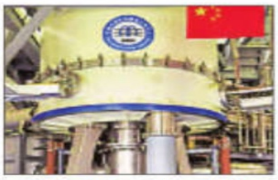

यूरोप के सामने चुनौती

यूरोप के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि विज्ञान से जुड़े कई क्षेत्रों में उसके पास बहुत सारे काम अधूरे पड़े हैं। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि राष्ट्रीय संवेदनशीलता या आपसी प्रतिबंधों के कारण यूरोपीय संघ के अंदर और यूरोप के शेष हिस्सों में भी बड़े बदलाव की कोशिशें अक्सर असफल हो जाती हैं। चीन का अविश्वसनीय और तेज गति से आगे बढ़ना, वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू-राजनीतिक संतुलन को पूरी तरह से बदल रहा है। जहां चीन अब अंतरराष्ट्रीय शोध एजंडे की दिशा तय कर रहा है, वहीं यूरोप भविष्य की प्रौद्योगिकियों की दौड़ में लगातार पिछड़ता जा रहा है।

Jansatta Page No-7

Dainik jaagaran Page No-3

Hindustan Page No-16

जानें-समझें

सीओपी30 जलवायु शिखर सम्मेलन

मिलकर समाधान खोजने की चुनौती

जनसत्ता संवाद

वैश्विक तापमान तेजी से बढ़ रहा है, समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। झीलें और जलधाराएं खतरे में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कटौती की योजना से जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के प्रयासों पर असर पड़ा है। कई सम्मेलनों में मिलकर समाधान ढूंढने की बात कही जाती रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह हो नहीं पाता। ऊपर से आर्थिक संकट की चुनौती भी है। ऐसे में ब्राजील के बेलेम में जलवायु शिखर सम्मेलन (सीओपी30) पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं।

बढ़ती चुनौती

जलवायु परिवर्तन से जनसंख्या और पर्यावरण पर भारी असर दिख रहा है। गर्म, तीव्र वैश्विक तापमान में केवल वृद्धि हो रही है, पहले से भी अधिक तेजी से वृद्धि हो रही है। 2025 के आंकड़ों से पता चला है कि प्रति दशक में औसत वैश्विक तापमान 0.27 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ रहा है। यह दर 1990 और 2000 के दशक से दोगुना है। समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ रहा है – पिछले दशक में लगभग 4.5 मिमी प्रति वर्ष बढ़ा। विश्व अब 2030 के आसपास 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि की सीमा को पार करने की राह पर है, जिसके बाद महासभा ने चेतावनी दी है कि हम विनाशकारी स्थितियों का सामना करेंगे। प्राक् औद्योगिक युग से अब तक विश्व में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो चुका है।

आर्थिक हालत

सोमवार 10 नवंबर से काप30 सम्मेलन शुरू हुआ है। यह 21 नवंबर तक चलेगा। यह सम्मेलन पेरिस समझौते के एक दशक पूरे होने के अवसर पर हो रहा है। यह बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों, चल रहे युद्धों और अमेरिकी शुल्क से उत्पन्न आर्थिक अनिश्चितता के बीच हो रहा है। आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा चिंताओं के बीच कई विकसित देशों द्वारा अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं का पुनर्मूल्यांकन करने के साथ-साथ अमेरिका के पेरिस समझौते से हटने के चलते इस वर्ष की जलवायु वार्ता के लिए एक चुनौतीपूर्ण पृष्ठभूमि तैयार हो गई है।

(फाइल फोटो)

शिखर सम्मेलन में वार्ताकार अपनी प्राथमिकताएं तय करेंगे और एक-दूसरे की स्थिति का आकलन करेंगे। विषय उभरने शुरू हो जाएंगे, जबकि देश और कंपनियां कार्य योजनाओं और परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण के वादों की घोषणा करेंगी। सीओपी में देश अपने राष्ट्रीय हित में समझौतों के लिए होड़ लगाते हैं और सीमा रेखाएं खींचते हैं। उम्मीद है कि वार्ता में सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे।

– भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री

यह शिखर सम्मेलन एक 'महत्त्वपूर्ण अवसर और एक गंभीर चुनौती' दोनों है और इससे एक मजबूत संकेत मिलना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय जलवायु संकट का सामना करने के अपने दृढ़ संकल्प में एकजुट है। अगर वैश्विक जलवायु व्यवस्था सिर्फ वादों का 'पिटारा' बनकर रह गई और कोई वास्तविक परिणाम सामने नहीं आये, तो जल्द ही इस जलवायु व्यवस्था पर बड़ा दबाव आ सकता है।

– अरुणाभ घोष, विशेष दूत, दक्षिण एशिया

क्या है सीओपी

सीओपी का अर्थ है 1992 की संयुक्त राष्ट्र जलवायु संधि पर हस्ताक्षर करने वाले पक्षों का सम्मेलन। इस संधि, जिसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) कहा जाता है, ने देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध किया। यह संगठन शिखर सम्मेलन का एजंडा तय करता है और साल भर सरकारों को साझा कार्रवाई और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एकजुट करने का काम करता है।

इस साल क्या है खास

इस वर्ष का 30वां जलवायु शिखर सम्मेलन एक पूर्ण-चक्र क्षण है। ब्राजील ने रियो पृथ्वी सम्मेलन की मेजबानी की थी, जहां 33 साल पहले संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस साल आदिवासी समूह भी शामिल हो रहे हैं। ब्राजील ने देशों से वादे पूरे करने को कहा है, जैसे कि सीओपी28 में जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को खत्म करना।

कटौती का असर

नासा अर्थ साइंस के वार्षिक बजट को आधा करके लगभग एक अरब डालर और एनओएए के खर्च में एक चौथाई से अधिक की कटौती करके 4.5 अरब डालर किया गया है। इसकी जलवायु अनुसंधान शाखा को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि, अन्य जगहों पर सार्वजनिक विज्ञान खर्च बढ़ रहा है, जिसमें चीन, ब्रिटेन, जापान और यूरोपीय संघ में विज्ञान अनुसंधान के लिए उल्लेखनीय बजट हैं।

पेरिस समझौते के बाद खाली हाथ

विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने गुरुवार को कहा कि 2025 दूसरा या तीसरा सबसे गर्म वर्ष होगा। वर्ष 2024 सबसे गर्म वर्ष था और ऐसा पहला वर्ष था जब वैश्विक औसत तापमान प्राक् औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक था। 2030 के दशक की शुरुआत तक दुनिया में तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री तक पहुंचने की बहुत संभावना है। दक्षिण एशिया, अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका सहित प्रमुख क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले दूतों के मुताबिक, 2015 के पेरिस समझौते के बाद से हुई प्रगति के बावजूद, तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए वैश्विक कार्रवाई अपर्याप्त है।

घटती उत्पादकता

वैश्विक एजंसियों का अनुमान है कि 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हर डिग्री तापमान पर श्रमिकों की उत्पादकता में 2-3 फीसद की गिरावट आ रही है। पिछले साल उत्पादकता में आई इस कमी से वैश्विक स्तर पर एक ट्रिलियन डालर से ज्यादा का नुकसान हुआ है। ब्रिटेन के इंपीरियल कालेज की एक टीम ने मृत्यु दर के रुझान का उपयोग करके इस गर्मी में लगभग 30% यूरोपीय आबादी में गर्मी से संबंधित 24,400 से अधिक मौत का अनुमान लगाया।

Jansatta Page No-7

अर्थशास्त्रियों से बजट पर बात

भाषा
नई दिल्ली, 10 नवंबर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियों को लेकर सोमवार को प्रमुख अर्थशास्त्रियों से मुलाकात की और आगामी बजट पर उनके विचार जाने। बैठक में साजिद चिनॉय, नीलकंठ मिश्रा, धर्मकीर्ति जोशी, रिधम देसाई, सोनल वर्मा और इंदिरा राजारमन मौजूद थे।

वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, 'केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (सोमवार) नयी दिल्ली में आगामी आम बजट 2026-27 के संबंध में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ परामर्श बैठक की अध्यक्षता की।'

इसमें कहा गया, 'बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के अलावा डीईए के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।'

सीतारमण के एक फरवरी को बजट पेश कर सकती हैं। वह वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताओं और भारत से निर्यात होने वाले सामान पर अमेरिका के 50 प्रतिशत के भारी शुल्क के बीच बजट पेश करेंगी। अगले वित्त वर्ष के बजट में मांग बढ़ाने, रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था को आठ प्रतिशत से अधिक की निरंतर वृद्धि दर पर लाने के मुद्दों पर ध्यान देना होगा। सरकार का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था 6.3 से 6.8 प्रतिशत के बीच बढ़ेगी।

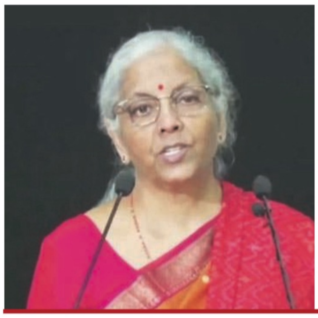

बजट की तैयारी

- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साजिद चिनॉय, नीलकंठ मिश्रा, धर्मकीर्ति जोशी, रिधम देसाई, सोनल वर्मा और इंदिरा राजारमन से बातचीत की
- सीतारमण वैश्विक अनिश्चितता और भारत से निर्यात होने वाले सामान पर अमेरिका के 50 प्रतिशत के भारी शुल्क के बीच बजट पेश करेंगी
- कृषि विशेषज्ञों ने अनुसंधान कार्यों के लिए अधिक धनराशि के साथ कृषि क्षेत्र के लिए मजबूत नीतिगत समर्थन की मांग की
- विशेषज्ञों ने फसल बीमा की नई अवधारणा तैयार करने की भी मांग की, क्योंकि अधिकांश किसान और राज्य इसके परिणामों से असंतुष्ट

कृषि क्षेत्र में आरऐंडडी के लिए अधिक धनराशि पर जोर

कृषि विशेषज्ञों ने सोमवार को जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चुनौतियों के बीच अनुसंधान कार्यों के लिए अधिक धनराशि के साथ कृषि क्षेत्र के लिए मजबूत नीतिगत समर्थन की मांग की। परामर्श के दौरान उद्योग और अनुसंधान संगठनों के एक दर्जन से अधिक कृषि विशेषज्ञों ने कृषि क्षेत्र की वृद्धि को मौजूदा स्तर से और बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।

बैठक में कृषि सचिव देवेश चौधरी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एमएल जाट, कृषि अर्थशास्त्री और उद्योग जगत के अंशधारकों ने भाग लिया। सूत्रों के अनुसार, 'बैठक सकारात्मक रही', जिसमें प्रतिभागियों ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डाला और सरकार से प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान करने की मांग की।

भारत कृषक समाज के अध्यक्ष अजय वीर जाखड़ ने कहा कि पिछले दो दशकों में कृषि में अनुसंधान और विकास के लिए धन आवंटन वास्तविक रूप से कम हुआ है, और उन्होंने इस धनराशि को दोगुना करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने फसल बीमा की नई अवधारणा तैयार करने की भी मांग की, क्योंकि अधिकांश किसान और राज्य इसके परिणामों से असंतुष्ट हैं।

बेरोजगारी दर में आई गिरावट

शिवा राजौरा
नई दिल्ली, 10 नवंबर

- किंतु युवाओं की बेरोजगारी दर दूसरी तिमाही में बढ़ी
- वेतनभोगी कर्मचारियों की रोजगार में हिस्सेदारी घटी

वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में श्रम बाजार में तेजी के कारण बेरोजगारी दर में कमी आई है, जबकि ज्यादा लोग काम की तलाश में आ रहे हैं। हालांकि युवा बेरोजगारों की संख्या में बढ़ोतरी और वेतनभोगी कामगारों की हिस्सेदारी में कमी चिंता का विषय बनी हुई है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा सोमवार को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए जारी तिमाही आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के आंकड़ों से पता चला है कि चालू साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) के संदर्भ में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के 5.4 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष2026 की दूसरी तिमाही में घटकर 5.2 प्रतिशत रह गई। सीडब्ल्यूएस में सर्वे की तारीख के पहले के 7 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर गतिविधियां निर्धारित की जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति को संदर्भ अवधि के दौरान 1 घंटे का भी काम नहीं मिला होता है तो उसे बेरोजगार माना जाता है, अगर वह काम की तलाश में हो।

आंकड़ों से यह भी पता चलता है ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर 4.8 प्रतिशत से घटकर 4.4 प्रतिशत रह गई है। वहीं शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर 6.8 प्रतिशत से मामूली बढ़कर 6.9 प्रतिशत हो गई है। दूसरी तिमाही के दौरान श्रम बल हिस्सेदारी दर (एलएफपीआर) घटकर 55.1 प्रतिशत हो गई है, जिसमें काम कर रहे या काम की मांग करने वाले लोग शामिल होते हैं। यह पहली तिमाही में 55 प्रतिशत थी।

Business Standard Page No-4

एक्सक्लूसिव. पहली बार प्रभात खबर में पढ़िए वोटिंग का जेंडर विश्लेषण

पहले चरण में 121 में 56 विधानसभा क्षेत्रों में पुरुषों से अधिक महिलाओं के वोट पड़े

- ओवरऑल महिला व पुरुष वोटों का अनुपात बराबर रहा, 50.01% पुरुष व 49.99% वोट महिलाओं के
- वोट प्रतिशत में महिलाएं रहीं काफी आगे, 61.56% पुरुष व 69.04% महिला वोटरों ने किया मतदान
- सारण, तिरहुत व कोसी इलाके में महिलाओं व पूर्वी बिहार, मगध व शाहाबाद के क्षेत्र में पुरुषों ने अधिक दिये वोट

अजय कुमार/संजय कुमार सिंह

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर छह नवंबर को 65.08 प्रतिशत वोट पड़े हैं, जिनमें महिलाओं और पुरुषों के वोट लगभग बराबर हैं. इनमें 50.01 प्रतिशत वोट पुरुषों के, जबकि 49.99% वोट महिलाओं के हैं. लेकिन, अगर हम मतदान प्रतिशत की बात करें, तो पुरुषों के मुकाबले महिलाएं काफी आगे रही हैं. जिलों से जुटाये गये आंकड़ों के अनुसार पहले चरण में 61.56 प्रतिशत पुरुष वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि 69.04 प्रतिशत महिला वोटरों ने मतदान किया. इस तरह महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से करीब 7.5 प्रतिशत अधिक रहा है. इस चरण में कुल 3.75 करोड़ वोटरों में से 2.44 करोड़ ने मतदान किया. वोट देने वालों में एक करोड़ 22 लाख 10 हजार 262 पुरुष और एक करोड़ 22 लाख चार हजार 271 महिलाएं शामिल हैं, जबकि पुरुषों वोटर की कुल संख्या 1.98 करोड़ और महिला वोटरों की कुल संख्या 1.76 करोड़ है.

अगर हम विधानसभा क्षेत्रवार देखें, तो 121 में से 56 सीटों पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के वोट अधिक पड़े हैं, जिनमें मुख्यतः मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सारण, सीवान, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया व बेगूसराय की सीटें हैं. इनमें मधेपुरा जिले की सिंहेश्वरस्थान, दरभंगा जिले की कुशेश्वरस्थान, गौड़ा बौराम व अलीनगर, गोपालगंज जिले की भोरे व हथुआ, खगड़िया जिले की अलौली सीट पर तो पुरुषों के मुकाबले आठ प्रतिशत या उससे अधिक महिलाओं के वोट पड़े हैं. सबसे अधिक कुशेश्वरस्थान सीट पर 12.72 प्रतिशत का अंतर है, जबकि अलीनगर में 10.2 प्रतिशत, गौड़ा बौराम में 9.88 प्रतिशत, भोरे में 9.3 प्रतिशत, सिंहेश्वरस्थान में 8.49 प्रतिशत, अलौली में 8.46 प्रतिशत और हथुआ में 8 प्रतिशत अधिक महिलाओं ने वोट डाले हैं. इस तरह सारण, तिरहुत और कोसी इलाके में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के अधिक वोट पड़े हैं.

जबकि शेष 65 सीटों में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों के अधिक वोट पड़े हैं. ये सीटें मुख्य रूप से मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर व बक्सर जिलों की हैं. इनमें पुरुष और महिला वोटों में सबसे अधिक अंतर पटना शहर की सीटों पर है. सबसे अधिक पटना जिले की फतुहा सीट पर 9.46 प्रतिशत का यह अंतर है, जबकि दानापुर में 9.08 प्रतिशत, पटना साहिब व बांकीपुर में 8.82 प्रतिशत, बिक्रम में 8.12 प्रतिशत, आरा में 8 प्रतिशत, फुलवारीशरीफ में 7.47 प्रतिशत, बख्तियारपुर में 7.45 प्रतिशत, दीघा में 7.44 प्रतिशत, मनेर में 6.84 प्रतिशत और बाढ़ में 6.3 प्रतिशत अधिक पुरुषों ने वोट डाले हैं. इस तरह पूर्वी बिहार, मगध व शाहाबाद क्षेत्र में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों के अधिक वोट पड़े हैं.

प्रभात खबर की टीम ने जिलों से जुटाये महिला-पुरुष वोटों के आंकड़े

क्रम	सीट	पुरुष	महिला	क्रम	सीट	पुरुष	महिला
1.	आलमनगर	47.69%	52.31%	29.	जीरादेई	46.80%	53.20%
2.	बिहारीगंज	46.75%	53.25%	30.	दरौली	47.49%	52.51%
3.	सिंहेश्वरस्थान	45.79%	54.21%	31.	रघुनाथपुर	47.08%	52.92%
4.	मधेपुरा	48.33%	51.67%	32.	दरौंदा	47.41%	52.59%
5.	सोनबरसा	46.94%	53.06%	33.	बड़हरा	46.80%	53.20%
6.	सिमरी बख्तियारपुर	47.01%	52.99%	34.	गोरियाकोठी	47.11%	52.89%
7.	महिषी	47.18%	52.82%	35.	महाराजगंज	48.10%	51.90%
8.	कुशेश्वर स्थान	43.64%	56.36%	36.	एकमा	48.56%	51.44%
9.	गौड़ा बौराम	45.06%	54.94%	37.	मांझी	49.09%	50.91%
10.	बेनीपुर	46.40%	53.60%	38.	बनियापुर	48.24%	51.76%
11.	अलीनगर	44.90%	55.10%	39.	तरैया	48.15%	51.85%
12.	दरभंगा ग्रामीण	46.58%	53.42%	40.	मढ़ौरा	48.88%	51.12%
13.	हायाघाट	46.99%	53.01%	41.	अमनौर	49.02%	50.98%
14.	बहादुरपुर	49.49%	50.51%	42.	परसा	48.97%	51.03%
15.	केवटी	47.22%	52.78%	43.	महुआ	49.79%	50.21%
16.	जाले	47.35%	52.65%	44.	राजापाकड़	49.75%	50.25%
17.	गायघाट	49.00%	51.00%	45.	पातेपुर	49.24%	50.76%
18.	औराई	48.14%	51.86%	46.	कल्याणपुर	49.75%	50.25%
19.	बरूराज	47.73%	52.27%	47.	वारिसनगर	49.38%	50.62%
20.	पारू	49.03%	50.97%	48.	मोहिउद्दीन नगर	49.88%	50.12%
21.	साहेबगंज	48.51%	51.49%	49.	विभूतिपुर	49.69%	50.31%
22.	बैकुंठपुर	47.65%	52.35%	50.	रोसड़ा	47.51%	52.49%
23.	बरौली	46.21%	53.79%	51.	हसनपुर	47.02%	52.98%
24.	गोपालगंज	46.59%	53.41%	52.	चेरिया बरियारपुर	48.68%	51.32%
25.	कुचायकोट	46.63%	53.37%	53.	बछवाड़ा	49.54%	50.46%
26.	भोरे	45.35%	54.65%	54.	बखरी	48.61%	51.39%
27.	हथुआ	46.00%	54.00%	55.	अलौली	45.77%	54.23%
28.	सीवान	48.27%	51.73%	56.	बेलदौर	48.27%	51.73%

Prabhat khabar Page No-5

फोटो – पीटीआई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला की अपनी राजकीय यात्रा के तीसरे दिन वहां की संसद के सदस्यों को संबोधित किया। मुर्मू ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. एंटोनियो अगोस्तिन्हो नेटो के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की तथा लुआंडा स्थित राष्ट्रीय सैन्य इतिहास संग्रहालय का भी दौरा किया। मुर्मू अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित इस देश की यात्रा करने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति हैं।

Business Standard Page No-7

विश्व परिक्रमा

ब्रिटेन : आव्रजन से निपटने को 'डेनमार्क माडल' पर विचार

जनसत्ता संवाद

ब्रिटेन की गृह मंत्री शबाना महमूद बढ़ते आव्रजन से निपटने के लिए 'डेनमार्क माडल' अपनाने पर विचार कर रही हैं, जिसमें कड़े नियंत्रण और शरण प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की योजना शामिल है। ब्रिटिश मीडिया ने यह खबर दी है। डेनमार्क को यूरोप में आव्रजन के मामले में सबसे कठोर देशों में से एक माना जाता है। खबर है कि महमूद ने हाल में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को डेनमार्क माडल का अध्ययन करने के लिए कोपेनहेगन भेजा है ताकि उस माडल को ब्रिटेन में लागू किया जा सके।

डेनमार्क संघर्षरत इलाकों से आकर सफलतापूर्वक शरण प्राप्त करने वाले अधिकांश लोगों को केवल अस्थायी आधार

पर ही तबतक रहने की अनुमति देता है जबतक सरकार उनके गृह देशों को उनके लौटने के लिए सुरक्षित घोषित नहीं कर देती।

डेनमार्क में पारिवार के आधार पर साथ रहने के लिए कड़े नियमों ने ब्रिटेन के गृह मंत्रालय के अधिकारियों का भी ध्यान आकर्षित किया है। इसमें वित्तीय आवश्यकताएं और जबरन विवाह को रोकने के लिए रहने के अधिकार के वास्ते 24 वर्ष से अधिक आयु सीमा और देश में प्रवासी बस्तियों के निर्माण को रोकने के लिए सख्त आवास नियम हैं।

'द संडे टाइम्स' के अनुसार, ब्रिटेन में रहने के इच्छुक शरणार्थियों को उच्च स्तर की अंग्रेजी सीखनी होगी और उनका कोई आपराधिक रेकार्ड नहीं होना चाहिए। शरण मिलने पर उन्हें अपने आवास और अन्य सुविधाओं का खर्च भी चुकाना पड़ सकता है। गृह मंत्रालय ने कम से कम 14 स्थानों की पहचान की है, जहां 10,000 प्रवासियों को रखा जा सकता है।

शोध

दुनिया में हर चौथा व्यक्ति साफ पानी से वंचित

जनसत्ता संवाद

विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की रपट में कहा गया है कि 10.6 करोड़ लोग सीधे नदियों, तालाबों या झीलों से पानी पीने को मजबूर हैं। पूरी दुनिया में अरबों लोग आज भी स्वच्छ व सुरक्षित पीने के पानी और बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं से वंचित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) और यूनिसेफ ने अपनी रपट 'प्रोग्रेस आन हाउसहोल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन 2000-2024: स्पेशल फोकस आन इनइक्वैलिटीज' में कहा है कि पिछले दस साल में कुछ प्रगति जरूर हुई है, लेकिन असमानताएं गहरी हैं और कमजोर समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।

रपट में कहा गया है कि हर चौथा व्यक्ति यानी करीब 2.1 अरब लोग सुरक्षित पीने के पानी से वंचित हैं। इनमें से 10.6 करोड़ लोग सीधे नदियों, तालाबों या झीलों से पानी पीने को मजबूर हैं।

केवल पानी ही नहीं, बल्कि 3.4 अरब लोग सुरक्षित शौचालय से भी वंचित हैं। इनमें से करीब 35.4 करोड़ लोग अब भी खुले में शौच करते हैं। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए खतरा है बल्कि सामाजिक गरिमा और सुरक्षा के लिए भी गंभीर समस्या है। 1.7 अरब लोगों के पास बुनियादी स्वच्छता सेवाएं भी नहीं हैं। इनमें से 61.1 करोड़ लोगों के पास तो हाथ धोने या स्वच्छता के लिए सुविधा नहीं है।

करीब 2.1 अरब लोग सुरक्षित पीने के पानी से वंचित हैं। इनमें से 10.6 करोड़ लोग सीधे नदियों, तालाबों या झीलों से पानी पीने को मजबूर हैं। केवल पानी ही नहीं, बल्कि 3.4 अरब लोग सुरक्षित शौचालय से भी वंचित हैं। इनमें से करीब 35.4 करोड़ लोग अब भी खुले में शौच करते हैं। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए खतरा है बल्कि सामाजिक गरिमा और सुरक्षा के लिए भी गंभीर समस्या है। 1.7 अरब लोगों के पास बुनियादी स्वच्छता सेवाएं भी नहीं हैं।

(फाइल फोटो)

यह समस्या हर जगह समान नहीं है। कम विकसित देशों में रहने वाले लोग बाकी देशों की तुलना में दो गुना ज्यादा बुनियादी पानी और शौचालय सेवाओं से वंचित हैं। इन्हें मूलभूत स्वच्छता सेवाओं की तीन गुना ज्यादा कमी झेलनी पड़ती है। नाजुक हालात वाले क्षेत्रों में सुरक्षित पानी की पहुंच बाकी देशों से 38 प्रतिशत अंक कम है। यानी गरीबी, असुरक्षा और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा कठिनाई झेलते हैं।

ग्रामीण इलाकों में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। 2015 से 2024 के बीच ग्रामीण इलाकों में सुरक्षित पानी की पहुंच 50 फीसद से बढ़कर 60 फीसद हो गई। इसी अवधि में बुनियादी हाथ धोने की सुविधा 52 फीसद से बढ़कर 71 फीसद हो गई। लेकिन शहरी क्षेत्रों में स्थिति लगभग जस की तस बनी हुई है। यानी गांवों में थोड़ी प्रगति हुई है, पर शहरों में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।

महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि महिलाएं और किशोरियां इस संकट का बोझ ज्यादा उठाती हैं। 70 देशों के आंकड़े दिखाते हैं कि अधिकांश महिलाओं और लड़कियों के पास माहवारी के समय बदलने के लिए जगह और सामग्री तो है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं। किशोरियां (15 से 19 वर्ष) माहवारी के दौरान अक्सर स्कूल, काम या सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं ले पातीं।

ज्यादातर देशों में महिलाएं और लड़कियां ही पानी लाने की जिम्मेदारी निभाती हैं। अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों में वे रोजाना 30 मिनट से ज्यादा समय पानी लाने में खर्च करती हैं। इसका सीधा असर उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर पड़ता है।

संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2030 तक यह लक्ष्य रखा है कि हर व्यक्ति को सुरक्षित पानी, शौचालय और स्वच्छता सेवाएं उपलब्ध हों। लेकिन मौजूदा गति से यह लक्ष्य पाना मुश्किल होता जा रहा है।

जहां तक भारत का सवाल है, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के मुताबिक, फरवरी 2025 तक, स्वच्छता सुविधाओं वाले 17 फीसदी घर मल-अपशिष्ट उपचार संयंत्रों से जुड़े थे। खासतौर पर खुले में शौच को खत्म करना और बुनियादी पानी व स्वच्छता सेवाएं हर व्यक्ति तक पहुंचाना अब भी संभव है, लेकिन इसके लिए सरकारों और संगठनों को बहुत तेजी से काम करना होगा।

‘खेल गांव’ में बदलेगा जेएलएन स्टेडियम

प्रमुख खेलों के अलावा खिलाड़ियों के लिए आवास की सुविधा भी होगी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 नवंबर।

राष्ट्रीय राजधानी स्थित प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन) स्टेडियम को ध्वस्त करके एक ‘खेल गांव’ बनाया जाएगा। इसमें सभी प्रमुख खेलों के अलावा खिलाड़ियों के लिए आवास की सुविधा भी होगी।

‘खेल गांव’ में मुख्य रूप से एक बहु-खेल सुविधा के साथ प्रशिक्षण, प्रमुख आयोजनों के संचालन के लिए विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध होता है। खेल मंत्रालय के एक सूत्र ने सोमवार को बताया कि स्टेडियम के 102 एकड़ क्षेत्र का पूरी तरह से पुनर्निर्माण किया जाएगा, लेकिन अभी तक यह योजना केवल एक प्रस्ताव है। इसलिए परियोजना की समय-सीमा और इसमें आने वाली लागत को लेकर कुछ भी तय नहीं है। जेएलएन स्टेडियम का निर्माण 1982 में आयोजित एशियाई खेलों के लिए किया गया था। इसने बाद में 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की, जिसके लिए इसे 900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पुनर्निर्मित किया गया था। इस स्टेडियम ने हाल ही में विश्व पैरा-एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की। इसके लिए इसमें मोंडो ट्रैक बिछा कर एक और नवीनीकरण किया गया था जिसमें 50 करोड़ की लागत आई थी।

फाइल फोटो।

खेल मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि स्टेडियम के 102 एकड़ क्षेत्र का पूरी तरह से पुनर्निर्माण किया जाएगा, लेकिन अभी तक यह योजना केवल एक प्रस्ताव है। **स्टेडियम** का निर्माण 1982 में आयोजित एशियाई खेलों के लिए किया गया था। इसने बाद में 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की।

मंत्रालय के सूत्र ने कहा कि स्टेडियम को ध्वस्त कर दिया जाएगा। स्टेडियम के अंदर स्थित सभी कार्यालय, जिनमें राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजंसी (नाडा) और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) शामिल हैं, स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। वर्तमान में इसके अंतर्गत आने वाली 100 एकड़ से अधिक भूमि का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। खेल गांव यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे पास प्रमुख खेलों के लिए मेजबानी की सुविधाएं, प्रशिक्षण सुविधाएं, प्रतिस्पर्धा करते समय एथलीटों के लिए आवास की व्यवस्था हो और यहां तक कि मनोरंजन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हों।

इस स्टेडियम में भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) का मुख्यालय भी है, जो इस स्थल का संचालक भी है। यहां सरकार की प्रमुख ‘खेलो इंडिया’ परियोजना का कार्यालय भी है। खेल गांव परियोजना के लिए शहरी विकास मंत्रालय सहित **बाकी पेज 8 पर**

Jansatta Page No-3

विश्व परिक्रमा

ब्रिटेन : आव्रजन से निपटने को ‘डेनमार्क माडल’ पर विचार

जनसत्ता संवाद

ब्रिटेन की गृह मंत्री शबाना महमूद बढ़ते आव्रजन से निपटने के लिए ‘डेनमार्क माडल’ अपनाने पर विचार कर रही हैं, जिसमें कड़े नियंत्रण और शरण प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की योजना शामिल है। ब्रिटिश मीडिया ने यह खबर दी है। डेनमार्क को यूरोप में आव्रजन के मामले में सबसे कठोर देशों में से एक माना जाता है। खबर है कि महमूद ने हाल में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को डेनमार्क माडल का अध्ययन करने के लिए कोपेनहेगन भेजा है ताकि उस माडल को ब्रिटेन में लागू किया जा सके।

डेनमार्क संघर्षरत इलाकों से आकर सफलतापूर्वक शरण प्राप्त करने वाले अधिकांश लोगों को केवल अस्थायी आधार पर ही तबतक रहने की अनुमति देता है जबतक सरकार उनके गृह देशों को उनके लौटने के लिए सुरक्षित घोषित नहीं कर देती।

डेनमार्क में पारिवार के आधार पर साथ रहने के लिए कड़े नियमों ने ब्रिटेन के गृह मंत्रालय के अधिकारियों का भी ध्यान आकर्षित किया है। इसमें वित्तीय आवश्यकताएं और जबरन विवाह को रोकने के लिए रहने के अधिकार के वास्ते 24 वर्ष से अधिक आयु सीमा और देश में प्रवासी बस्तियों के निर्माण को रोकने के लिए सख्त आवास नियम हैं।

‘द संडे टाइम्स’ के अनुसार, ब्रिटेन में रहने के इच्छुक शरणार्थियों को उच्च स्तर की अंग्रेजी सीखनी होगी और उनका कोई आपराधिक रेकार्ड नहीं होना चाहिए। शरण मिलने पर उन्हें अपने आवास और अन्य सुविधाओं का खर्च भी चुकाना पड़ सकता है। गृह मंत्रालय ने कम से कम 14 स्थानों की पहचान की है, जहां 10,000 प्रवासियों को रखा जा सकता है।

Jansatta Page No-7

समय का अधिकतम लाभ उठाएं

एक ऐसा क्षण क्या आपने कभी अनुभव किया है, जिसने आपकी सोच को पूरी तरह बदल दिया हो? स्वेट मार्डन, प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक, ने ऐसा ही एक क्षण अनुभव किया, जिससे उनमें दर्शनशास्त्र के प्रति गहरी रुचि जागी. एक दिन उन्होंने एक प्रभावशाली चित्र देखा, जिसमें एक व्यक्ति का चेहरा बालों से ढका हुआ था और उसके पैरों के नीचे पंख थे. उस चित्र के नीचे लिखा था, 'मैं समय हूं, कोई मुझे देख नहीं सकता, पर मैं उड़ता रहता हूं.' यह अद्भुत छवि इस बात का सशक्त अनुस्मारक है कि समय किस प्रकार आगे बढ़ता रहता है, अदृश्य किंतु बिना रुके. हर सुबह हमें 1,440 अनमोल मिनट देती है, जो संभावनाओं और अवसरों से भरे होते हैं. जो इन मिनटों का पूरा उपयोग करते हैं, वे सफलता की नींव रख पाते हैं. जो अपना समय तुच्छ कार्यों में व्यर्थ करते हैं, वे दिन के अंत में अधूरे कार्यों और अपूर्ण लक्ष्यों के साथ रह जाते हैं. वेदों में कहा गया है : 'क्षणसः क्षणसोविद्या कणसः कणसो धनम्.' अर्थात, 'एक-एक पैसे को जोड़ कर ही लोग अरबपति बनते हैं. और एक-एक क्षण का उपयोग करके ही कोई विद्वान बनता है.' समय वास्तव में एक सीमित संसाधन है. आइए, हम यह रहस्य जानें कि हर एक मिनट में बुद्धिमानी से कैसे निवेश किया जाये. मानव जीवन की क्षणभंगुरता को याद करके दीर्घसूत्रता पर काबू पायें. दीर्घसूत्रता एक सार्वभौमिक संघर्ष है, जो हमारी प्रगति में बाधा डालती है. हम सभी के पास एक दिन में समान 24 घंटे होते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं. वस्तुतः, हम हर दिन जो कुछ कार्य करते हैं, उनमें से कुछ ही बड़ा फर्क लाते हैं, जबकि अधिकांश अधिक प्रभाव नहीं डालते. इस विचार को पैरेटो सिद्धांत या 80/20 नियम कहा जाता है. कुंजी यह है कि हमें जीवन में सबसे अधिक फर्क लाने वाले कुछ अर्थपूर्ण (20) लक्ष्यों को रखना है और वास्तव में महत्वहीन अनेक (80) चीजों में नहीं उलझना है. ऐसा करके हम अपने प्रयासों को अनुकूलित कर सकते हैं और बिना थकावट के महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त कर सकते हैं.

-स्वामी मुकुंदानंद

Prabhat khabar Page No-8

Hindustan Page No-10

दो लाख से ज्यादा आबादी वाले सभी कस्बों में खुलेंगे सहकारी बैंक : शाह

केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने दिल्ली में किया दो दिवसीय 'को-आप कुंभ' का उद्घाटन

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो: देश की सहकारिता प्रणाली अब शहरी ढांचे में नई ऊर्जा के साथ विस्तार की ओर बढ़ रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दिल्ली में आयोजित 'को-आप कुंभ' का उद्घाटन करते हुए कहा कि पांच वर्षों में दो लाख से अधिक आबादी वाले हर शहर में कम से कम एक शहरी सहकारी बैंक स्थापित किया जाएगा। यह अभियान न केवल वित्तीय निवेश की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि रोजगार सृजन और छोटे उद्यमियों के सशक्तीकरण का माध्यम भी बनेगा। सहकारिता कोई सरकारी योजना नहीं, बल्कि

नई दिल्ली में 'को-आप कुंभ 2025' के उद्घाटन अवसर पर संबोधित करते केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह। ● एएनआइ

समाज की आत्मा है। यह आंदोलन जितना पारदर्शी, अनुशासित और तकनीक-सक्षम बनेगा, उतना ही विकास माडल को मजबूत करेगा।

अमित शाह ने इस दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 'सहकार डिजी-पे' और 'सहकार डिजी-लोन' मोबाइल एप की शुरुआत करते कहा कि कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते भारत में डिजिटल भुगतान समय की मांग है। शहरी सहकारी बैंकों को प्रतिस्पर्धा में टिके रहना है तो डिजिटल लेन-देन अपनाना ही होगा। उन्होंने दो वर्षों में डेढ़ हजार शहरी सहकारी बैंकों के इस प्लेटफार्म से जुड़ने का लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सहकारी संस्थाओं के तकनीकी सशक्तीकरण और वित्तीय अनुशासन को प्राथमिकता दे रही है। पिछले दो वर्षों में शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। एनपीए 2.8 प्रतिशत से घटकर 0.6 प्रतिशत रह गई हैं।

सहकारिता मंत्री ने राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक एवं ऋण समितियों महासंघ (नेफक्यूब) से आग्रह किया कि वह क्षेत्रीय असमानता को खत्म करने और छोटे शहरों तक बैंकिंग पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करे। उन्होंने कहा कि सहकारिता राज्यों का विषय है। फिर भी केंद्र ने नीतिगत मार्गदर्शन देकर एकरूपता सुनिश्चित की है। प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) के माडल अब लगभग सभी राज्यों ने स्वीकार कर ली हैं, जिससे इनके कंप्यूटरीकरण और सेवाओं के विस्तार का रास्ता खुला है।

Dainik Jagaran Page No-12

रुपया छह पैसे गिरकर 88.71 प्रति डालर पर

मुंबई, 10 नवंबर (भाषा)।

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के दबाव में सोमवार को अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार के सुस्त कारोबारी सत्र में रुपया छह पैसे गिरकर 88.71 (अस्थायी) प्रति डालर पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि हालांकि, सकारात्मक घरेलू शेयर बाजार और कमजोर डालर ने रुपए की गिरावट पर अंकुश लगा दिया।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में, रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 88.64 पर खुला और दिन के दौरान इसने डालर के मुकाबले 88.64 के उच्चतम स्तर और 88.71 के निचले स्तर को छुआ। घरेलू मुद्रा अंततः 88.71 (अस्थायी) पर बंद हुई, जो पिछले बंद भाव से छह पैसे की गिरावट है। शुक्रवार को, रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले दो पैसे गिरकर 88.65 रह गया था।

सोना 1,300 रुपए बढ़कर 1,25,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर

मजबूत वैश्विक संकेतों और कमजोर डालर के बीच सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 1,300 रुपए बढ़कर 1,25,900 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी। 99.5 फीसद शुद्धता वाले सोने की कीमत शुक्रवार के 1,24,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की तुलना में 1,300 रुपए बढ़कर 1,25,300 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) हो गई।

स्थानीय सर्राफा बाजार में, पिछले बाजार सत्र में 99.9 फीसद शुद्धता वाला सोना 1,24,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

Jansatta Page No-10

भारत की खेल शक्ति को नई उड़ान देगी स्पोर्ट्स सिटी

नई दिल्ली, जेएनएन: नई दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम को तोड़कर केंद्र सरकार ने इसकी 102 एकड़ की भूमि को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को इस आशय का प्रस्ताव रखा। स्पोर्ट्स सिटी ऐसे आधुनिक शहर या क्षेत्र को कहा जाता है जो खेलों की पूरे इकोसिस्टम के विकास के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य केवल स्टेडियम बनाना नहीं, बल्कि ऐसा समग्र खेल केंद्र तैयार करना होता है जहां खिलाड़ी, प्रशिक्षक, दर्शक और खेल उद्योग सबको विकसित होने का अवसर मिले।

विश्व की प्रमुख स्पोर्ट्स सिटीज

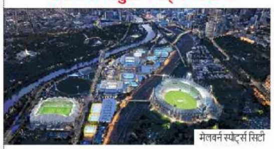

मेलबर्न स्पोर्ट्स सिटी

1 मेलबर्न स्पोर्ट्स सिटी (आस्ट्रेलिया) : आस्ट्रेलिया की मेलबर्न स्पोर्ट्स सिटी को स्पोर्टिंग कैपिटल आफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसमें एक लाख दर्शक क्षमता वाला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, फुटबाल स्टेडियम, आस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन करने वाला मेलबर्न पार्क, फुटबाल व रग्बी को समर्पित आमी पार्क, आस्ट्रेलियन ग्रांप्रि के लिए अल्बर्ट पार्क सर्किट स्थित है। इसके अलावा शहर के लगभग हर इलाके में जिम, स्विमिंग सेंटर और कोचिंग हब हैं।

2 दुबई स्पोर्ट्स सिटी (यूएई) : यह दुनिया की सबसे आधुनिक स्पोर्ट्स सिटी में से एक है। इसमें आइसीसी क्रिकेट अकादमी, फुटबाल क्लब, गोल्फ कोर्स और मल्टी स्पोर्ट्स कांप्लेक्स शामिल हैं। यहां विश्व स्तरीय टूर्नामेंटों के साथ-साथ कार्पोरेट स्पोर्ट्स और पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाता है।

3 कतर स्पोर्ट्स सिटी (दोहा): दोहा की स्पोर्ट्स सिटी 617 एकड़ में फैली है, जिसमें फुटबाल, एक्वाटिक्स, 13 इंडोर खेल एरीना, एक खेल अकादमी और खेल चिकित्सा अस्पताल शामिल हैं। एस्पायर जोन के नाम से प्रसिद्ध इसमें एस्पायर अकादमी, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम और हमाद एक्वाटिक सेंटर शामिल हैं। यहां सुविधाएं फुटबाल विश्व कप 2022 की मेजबानी के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों पर तैयार की गईं।

दोहा एस्पायर जोन

4 लंदन ओलिंपिक पार्क (यूके) : 2012 ओलिंपिक के बाद इसे स्थायी स्पोर्ट्स सिटी में बदला गया। अब यह स्थानीय खेल प्रतिभा के प्रशिक्षण, पर्यटन और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र है। इसमें स्टेडियम के साथ-साथ एथलीट विलेज, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, और इवेंट स्पेस शामिल हैं।

5 बीजिंग ओलिंपिक स्पोर्ट्स सिटी (चीन) : 2008 बीजिंग ओलिंपिक के लिए बनाया गया बर्ड नेस्ट स्टेडियम और वाटर क्यूब जैसी प्रतिष्ठित इमारतें इसी के अंतर्गत आती हैं। यह शहर अब अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों और खेल शिक्षा का बड़ा केंद्र बन चुका है।

बीजिंग बर्ड नेस्ट स्टेडियम

6 बार्सिलोना (स्पेन): 1992 ओलिंपिक के बाद से शहर ने खुद को एक स्पोर्ट्स-टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया। यहां खेल सुविधाओं के साथ-साथ फिटनेस और सामुदायिक भागीदारी को भी प्राथमिकता दी गई।

स्पोर्ट्स सिटी की मुख्य विशेषताएं

मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम : फुटबाल, क्रिकेट, हाकी, एथलेटिक्स, तैराकी, बैडमिंटन जैसे खेलों के लिए अलग-अलग स्टेडियम और इंडोर एरीना।

स्पोर्ट्स साइंस और फिटनेस सेंटर: आधुनिक टेक्नोलाजी से सुसज्जित लैब, जहां खिलाड़ियों की फिटनेस, पोषण, और पुनर्वास पर काम होता है।

खेल पर्यटन व मनोरंजन : दर्शकों के लिए होटल, रेस्टोरेंट, थीम पार्क, और म्यूजियम जो खेल संस्कृति को बढ़ावा देते हैं।

स्पोर्ट्स सिटी के लाभ

- स्थानीय खिलाड़ियों को उच्च स्तर की सुविधाएं और ट्रेनिंग मिलती है।
- निर्माण, इवेंट मैनेजमेंट, कोचिंग, होटलिंग और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में नौकरियां बढ़ती हैं।
- देश-विदेश के दर्शक खेल देखने आते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को लाभ होता है।

Dainik Jagaran Page No-10

Hindustan Page No-8

अन्य राज्यों में नहीं दिखेगा एसआइआर पर बिहार जैसा विरोध : रावत

सप्ताह का साक्षात्कार

क्या बिहार जितने नाम पहले भी कभी मतदाता सूची से हटाए गए थे?

पुनरीक्षण में इससे ज्यादा नाम हटते रहे हैं। 2023 में मतदाता सूची के शुद्धिकरण को लेकर देशभर में एक बड़ा अभियान चलाया गया था। इसमें मतदाता सूची में होने वाली नेचुरल बढ़ोत्तरी की जगह मतदाताओं की संख्या करीब छह प्रतिशत तक कम हो गई थी।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर एक बार फिर घमासान शुरू हो गया है। बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में इसका तीखा विरोध हो रहा है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगाई गई है। लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर विपक्ष के हमलों को झेल चुके पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत का मानना है कि एसआइआर के खिलाफ बिहार जैसा विरोध बंगाल और तमिलनाडु समेत 12 राज्यों में नहीं देखने को मिलेगा। बिहार से सीख लेते हुए चुनाव आयोग ने इस बार फार्म के साथ दस्तावेज देने की बाध्यता खत्म कर दी है। उन्होंने कहा कि एसआइआर कराने का अधिकार चुनाव आयोग को है लेकिन वोट चोरी जैसे मुद्दे पर चुनाव आयोग को ज्यादा संवेदशीलता और पारदर्शिता से काम करना चाहिए। पूर्व सीईसी रावत से दैनिक जागरण के विशेष संवाददाता अरविंद पांडेय ने एसआइआर के मुद्दे पर विस्तार से बात की। पेश से प्रमुख अंश-

● कांग्रेस ने मतदाता सूची में गड़बड़ी को बड़ा मुद्दा बना लिया है। क्या पहले भी यह मुद्दा बना था?

-2018 में यह मुद्दा काफी उठा था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ऐसे मुद्दे उठे थे। इस तरह की शिकायतों के बाद आयोग ने डुप्लीकेट, एक जैसे चेहरों वाले मतदाताओं की पहचान के लिए दो साफ्टवेयर खरीदे। इससे बड़ी संख्या में एक जैसे मिलते-जुलते नाम व चेहरे वाले मतदाता निकाले गए। अकेले मध्य प्रदेश में इसके जरिए 60 लाख डुप्लीकेट मतदाता पकड़े गए थे।

● आपके समय में राजनीतिक दलों ने ईवीएम को मुद्दा बनाया था और अब मतदाता सूची को। ये आयोग पर दबाव बनाने का हथकंडा है?

-ऐसा नहीं है। असलियत यह है कि राजनीतिक दलों के पास किसी आरोप की जांच के लिए कोई साधन नहीं है। उन्हें तो अपने कार्यकर्ताओं की बात पर भरोसा करना होता है। ये उनकी मजबूरी है। लेकिन चुनावी मशीनरी की ये मजबूरी नहीं है। किसी भी मुद्दे पर जांच के लिए तैयार रहना चाहिए। सभी को जांच में शामिल करना चाहिए, ताकि उन्हें भरोसा रहे कि जांच सही हुई है। जो भी निष्कर्ष निकले, उसे उनसे साझा करें और उसे सार्वजनिक करें। ईवीएम के मामले में ऐसा ही किया गया था। आम आदमी पार्टी ने उस समय आरोप लगाया था। आयोग ने तुरंत उस पर संज्ञान लिया और कहा कि हमारे सुरक्षाकर्मियों के साथ चलें, जहां भी संदेह हो, हम वहां से उन ईवीएम को उठाकर लाएंगे। इस चैलेंज के बाद कोई राजनीतिक दल आगे नहीं आया।

● कांग्रेस मशीन रिडेबल मतदाता सूची मांग रही है और चुनाव आयोग उसे दे नहीं रहा है। क्या आयोग का फैसला सही है?

-रिडेबल मतदाता सूची सुरक्षा कारणों से किसी को नहीं दी जा सकती है। चुनाव आयोग की गलती यह है कि वह मतदाता सूची में गड़बड़ी से जुड़ी राजनीतिक दलों की किसी भी शिकायत पर तुरंत जांच से बच रहा है। शपथ पत्र मांग रहा है। आयोग को शिकायत पर अपने पास मौजूद मशीन रिडेब्रल से तुरंत जांच कर शिकायत करने वाले को सही तथ्य बताना चाहिए। इससे शिकायत का निराकरण भी होगा और डाटा भी सुरक्षित रहेगा।

● एसआइआर पहले भी हुए मगर पहली बार ऐसा विरोध हो रहा, क्यों?

-आजादी के बाद 2003 तक सात या आठ बार एसआइआर हो चुके हैं। लेकिन कभी एसआइआर को लेकर विवाद नहीं हुआ। पहले कभी नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र भी नहीं मांगा गया। सिर्फ गणना फार्म सभी को भरना था। बाद में संदेह होने पर नागरिकता के दस्तावेज मांगे जाते थे। इस बार नागरिकता का मुद्दा नागरिकों पर डाल दिया गया। यह विवाद और विरोध की बड़ी वजह बना।

● राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, क्या चुनाव आयोग वोट चोरी करा सकता है?

-ये चीज राजनीतिक है। आयोग पर वोट चोरी के आरोप पहले कभी नहीं लगाए गए। आयोग की सदैव नीति रही कि कोई भी राजनीतिक दल या मतदाता शिकायत करता था तो एक मिनट की देरी किए बगैर तुरंत जांच कराता था। इसमें शिकायतकर्ता और सभी राजनीतिक दलों को शामिल किया जाता था। अगले ही दिन बता दिया जाता था कि असलियत क्या है। इससे किसी को हल्ला करने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन इस बार जांच के लिए शपथ पत्र देने को कहा गया। जब सभी क्षेत्र में डी-क्रिमनलाइजेशन की बात की जा रही है, तब आयोग का यह रवैया सही नहीं है। शपथ पत्र मांगना क्रिमनलाइजेशन जैसी चीज ही है। यदि एक भी गलती हुई तो छह महीने की सजा होगी।

- **चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप राजनीतिक, ऐसे आरोप पहले कभी नहीं लगाए गए**
- **इस बार चुनाव आयोग ने बीएलए को कुछ ज्यादा ही अधिकार दे दिए**

● जिस मतदाता सूची को लेकर पूरा विवाद है, उसे बीएलओ तैयार करते हैं। इनकी नियुक्ति को लेकर कोई मानक है? इनके प्रशिक्षण पर कितना जोर दिया जाता है और गड़बड़ी पर क्या कार्रवाई होती है?

-ये स्थानीय और उसी क्षेत्र के रहने वाले होने चाहिए। सरकारी कर्मचारी होने चाहिए। साथ ही उस क्षेत्र, मोहल्ले की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जिनका निवास कहीं और है और ड्यूटी कहीं और है तो उन्हें इसमें नहीं लगाया जाता है। इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। मौजूदा आयोग ने तो इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है। इन्हें दिल्ली में बुलाकर प्रशिक्षण देने का काम किया है। उन्हें टैबलेट दिया जाता है। बीएलओ कोई गड़बड़ी करता है तो उन्हें बर्खास्त भी किया जा जाता है। आयोग का मानना था कि जब भी किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत मिले तो तुरंत इसकी जांच कराई जाए।

● एसआइआर के दौरान बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) का नाम भी चर्चा में है। चुनावी प्रक्रिया में इनकी क्या उपयोगिता होती है और ये कितने सक्रिय रहते हैं?

-इस बार चुनाव आयोग ने बीएलए को कुछ ज्यादा अधिकार दे दिए। उन्हें फार्म लाकर जमा करने का अधिकार दे दिया। उन्हें बीएलओ के साथ बैठने का अधिकार दिया। ये पहले कभी नहीं हुआ। आयोग पहले राजनीतिक दलों और उससे जुड़े लोगों को सिर्फ बुलाता था लेकिन काम में उन्हें कोई भागीदारी नहीं दी जाती थी क्योंकि ये स्टेक होल्डर हैं। ये अपने-अपने काम करेंगे। ये ठीक नहीं है। बीएलओ को सिर्फ इतनी भूमिका देनी चाहिए कि वह उपस्थित रहें और गड़बड़ी पर नजर रखे। चुनाव आयोग ने पहले निर्देश निकाला था कि एक व्यक्ति से एक फार्म ही लिया जाएगा। अब बीएलए से कहा जा रहा है कि वह 50 फार्म लाकर जमा करा सकता है।

Dainik Jagaran Page No-12

भूटान को चीनी चंगुल से बचाने की चुनौती

श्रीराम चौलिया

तिब्बत में चीन के अतिक्रमण और नेपाल में चीन के विस्तार को देखते हुए भारत के लिए भूटान को चीनी महत्वाकांक्षाओं से बचाकर रखना अनिवार्य है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो दिन के लिए भूटान के दौरे पर हैं। भूटान क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा पड़ोसी है, परंतु इसका सामरिक महत्व अत्यधिक है, क्योंकि यह चीनी कब्जे वाले तिब्बत और भारत के बीच ऊंचे हिमालयों में स्थित महत्वपूर्ण मध्यवर्ती देश है। गत 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी का वहां चार बार जाना और इसी तरह भूटान के प्रधानमंत्रियों और राजाओं का लगातार भारत में आगमन का क्रम दर्शाता है कि इस संवेदनशील रिश्ते को उचित ही सर्वोच्च राजनीतिक महत्व दिया जा रहा है। भूटान अगर कमजोर और बेसहारा बन जाए तो विस्तारवादी चीन न केवल उसे निगल जाएगा, बल्कि भारत की सीमा पर एक और मोर्चा खोल देगा। 1950 के दशक में तिब्बत में चीन के अतिक्रमण और वर्तमान में नेपाल में चीन के विस्तार को देखते हुए भारत के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि भूटान को चीनी महत्वाकांक्षाओं से बचाकर रखे। एक अद्वितीय हिमालयी बौद्ध राष्ट्र को आक्रामक महाशक्ति चीन के जबरन कब्जे से बचाना कोई किताबी या सैद्धांतिक मुद्दा नहीं है। 'सीलाइट' नामक अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थान के अनुसार हाल के वर्षों में चीन ने भूटान की पारंपरिक सीमाओं के भीतर कम से कम 22 कृत्रिम गांव बसाए हैं, जो इस छोटे से देश के लगभग दो प्रतिशत भूभाग पर कब्जा हैं। इन चीनी बस्तियों में सड़कें, सैन्य चौकियां और प्रशासनिक केंद्र भी शामिल हैं, जिससे जमीनी स्तर पर ऐसे नए तथ्य अंकित कर दिए गए हैं, जिन्हें नकारना मुश्किल है।

भूटान के साथ सीमा वार्ताओं के अंतर्गत चीन ने नए दावे भी पेश किए हैं, ताकि भूटान की संप्रभुता धीरे-धीरे घिस जाए और चीनी सेना भारत की सीमाओं को घेर ले। 2017 में डोकलाम में अवैध सड़क निर्माण का प्रयास चीन की दीर्घकालिक योजनाओं का नमूना था। इसी खतरे को रोकने के लिए भारतीय सेना ने 73 दिन तक चीनी फौज से आमना-सामना किया था। अंततः चीन को डोकलाम से पीछे हटना पड़ा था।

भूटान के अस्तित्व के लिए चीन के बढ़ते खतरे के चलते भारत भूटानी सेना के लिए रक्षा उपकरणों के साथ प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ा रहा है। 2007 में संशोधित भारत-भूटान स्थायी मैत्री संधि के अनुसार दोनों देश ''राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों'' का मुकाबला करेंगे। चीन द्वारा भूटान में घुसपैठ करने और उसे अपने अधीन लाने के मंसूबों के कारण प्रतिरक्षा भारत-भूटान संबंधों का प्रमुख स्तंभ बना रहेगा। चूंकि भूटान को भारतीय सैन्य सहायता संवेदनशील मामला है, इसलिए उसके बारे में सार्वजनिक रूप से घोषणाएं नहीं होती हैं। इस सबके बाद भी मोदी सरकार भूटान के उत्तर और पूर्व में मंडरा रहे खतरे से अवगत है और उसे जरूरी संसाधन उपलब्ध करा रही है।

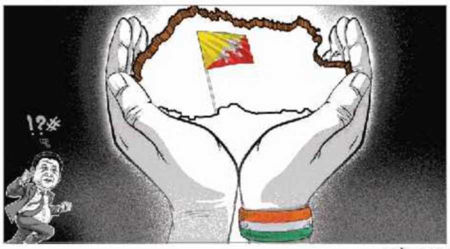

अवधेश राजपूत

भूटान को अपने प्रभाव में लाने के इरादे से चीन उसे आर्थिक प्रलोभन भी दे रहा है। दक्षिण एशिया में भारत के पड़ोसियों में भूटान एकमात्र देश है, जो चीन की 'बेल्ट एंड रोड' पहल में शामिल नहीं हुआ है। ऐसे में भूटान की आर्थिक प्रगति, ढांचागत सुधार और आधुनिकीकरण के प्रति भारत का विशेष उत्तरदायित्व है। भूटान की अपनी चौथी यात्रा में मोदी भारत की मदद से बने पुनतसंगचु जलविद्युत परियोजना का अनावरण करेंगे, जिससे भारत को भूटान से बिजली का निर्यात और भूटान में भारतीय कंपनियों का निवेश बढ़ेगा। भारत अपने उत्तर-पूर्वी राज्य असम के कोकराझार से भूटान के प्रतिष्ठित 'न्यू गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी' तक 58 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का भी निर्माण कर रहा है, जिससे आपसी कारोबार और पर्यटन का विकास होगा।

अंतरिक्ष उपग्रहों से लेकर वित्तीय प्रौद्योगिकी तक भारत उभरते क्षेत्रों में भूटान की मदद कर रहा है, ताकि उसके विभिन्न राजनीतिक समूह और सामाजिक वर्ग भारत के साथ मित्रता के ठोस लाभ को महसूस कर सकें। वर्षों से भूटान भारतीय सहायता का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है। 2025-26 के भारतीय बजट में उसके लिए 2,150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। मोदी की भूटान यात्रा दुनिया को याद दिलाएगी कि भारत दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के लिए प्रमुख साझीदार बनने के लिए तत्पर है और इस मामले में चीन से प्रतिस्पर्धा करने से नहीं कतराएगा।

विकास और प्रतिरक्षा के अलावा भारत ने संस्कृति और आध्यात्मिकता को अपनी भूटान नीति का तीसरा स्तंभ बनाया है। भूटान की इस यात्रा के दौरान मोदी एक मठ में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पूजा करेंगे, जिन्हें उत्तर प्रदेश के पिपरहवा से वहां भेजा गया है। इसके अलावा भारत की ओर से बौद्ध आध्यात्मिक नेता और भूटानी राष्ट्र के संस्थापक झाबद्रुंग नामग्याल की प्रतिमा भी भूटान को प्रदर्शन के लिए दी गई है।

भूटान की आठ लाख से भी कम आबादी अत्यंत धर्मपरायण है और अपनी अद्वितीय बौद्ध विरासत के संरक्षण के प्रति सचेत है। एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में उभरकर भारत भूटान के लोगों का दिल और दिमाग जीत रहा है। बिना कहे ही सब समझते हैं कि जहां नास्तिक चीन ने अधिकृत तिब्बत में बौद्ध धर्म के विरुद्ध सांस्कृतिक नरसंहार किया, वहीं दूसरी ओर लोकतांत्रिक भारत ने सदियों पुरानी आध्यात्मिक कुंजी को संरक्षित किया। इसीलिए मोदी अपनी इस भूटान यात्रा में एक विशेष 'वैश्विक शांति प्रार्थना' समारोह में भी भाग ले रहे हैं, जो दोनों देशों की सरकारें साझा तौर पर आयोजित कर रही हैं। भारत की रणनीति इन सभी आयामों पर ध्यान देने की है, ताकि भूटानी समाज में कोई भारत विरोधी गुट न सक्रिय होने पाए। यह संयोग नहीं कि भूटान भारत का सबसे स्थिर दक्षिण एशियाई पड़ोसी है। संगठित भारत-विरोधी तत्वों की अनुपस्थिति के फलस्वरूप भूटान में सामाजिक समरसता में खलल नहीं पड़ा है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव की तरह भूटान में भी चीन घुसपैठ करके भारत-विरोधी भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है। भविष्य में चीनी कारस्तानियों से निपटने के लिए भारत को भूटानी विशिष्ट वर्ग के साथ-साथ आम लोगों से भी घनिष्ठ संबंध बनाने होंगे। मोदी बार-बार भूटान जाते रहे तो दोनों देशों की मित्रता यूं ही सुदृढ़ होती रहेगी।

(लेखक जिंदल स्कूल आफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर और डीन हैं)
response@jagran.com

Dainik Jagaran Page jhankar -6

Dainik Jagaran Page No-11

बैंकों से बेहतर है सहकारी नेटवर्क

बढ़ई, कुम्हार, सुनार और दर्जी आदि 18 पारंपरिक पेशे से जुड़े लोगों के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एक नई उम्मीद लेकर आई थी। इसके तहत इन्हें कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक औजार और बिना जमानत के छोटा ऋण देने का प्रविधान है, ताकि वे आज की तकनीकी दुनिया में फिर से खड़े हो सकें। सितंबर 2023 में 13,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू हुई इस योजना का लक्ष्य देश के ग्रामीण जीवन से संबंधित पारंपरिक पेशे थे। दो साल बाद कागज पर तो आंकड़े उत्साहजनक दिखते हैं, क्योंकि इस योजना के तहत तीन करोड़ से ज्यादा पंजीकरण हुए हैं, पर सच्चाई कुछ और है। अब तक सिर्फ 4.65 लाख कारीगरों को 4,000 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत हुए हैं, जिनमें 2,200 करोड़ रुपये ही वास्तव में वितरित हुए और मात्र 224 करोड़ रुपये की वापसी हुई है। पंजीकरण और वास्तविक कर्ज वितरण के बीच यह फासला सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि संरचनात्मक कमी दर्शाता है। यह बताता है कि भारत में आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं का सबसे बड़ा रोड़ा बैंकिंग व्यवस्था ही है।

निजी बैंक सरकार का विरोध नहीं कर रहे, बस नियमों का चतुराई से पालन कर रहे हैं। आरबीआइ ने सभी बैंकों को आदेश दिया है कि वे अपनी कुल ऋण पुस्तिका का 40 प्रतिशत कृषि, लघु उद्योग क्षेत्र के साथ कमजोर वर्गों को दें। निजी बैंक प्राथमिकता क्षेत्र के लिए निर्धारित ऋण लक्ष्य को पूरा करने के बजाय प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र खरीद लेते हैं। ये प्रमाणपत्र वे उन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से खरीद सकते हैं, जिन्होंने अपने लक्ष्य से अधिक ऋण वितरित किया हो। कुछ बैंक अपने दायित्व को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों या माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के माध्यम से पूरा करने का दावा करते हैं। कागज पर वे नियम पूरा करते हैं, लेकिन हकीकत में विश्वकर्मा ऋण देने के मामले में निजी बैंकों का रिकार्ड निराशाजनक है। पीएम जन धन योजना में भी निजी बैंकों की हिस्सेदारी मुश्किल से तीन प्रतिशत है। निजी बैंकों का तर्क है कि दो लाख रुपये का एक छोटे कारीगर को दिया गया ऋण उतने ही कागजी काम और लागत मांगता है, जितना 20 लाख का कार लोन, पर मुनाफा बहुत कम। कारीगरों के पास न जमानत होती है, न डिजिटल ऋण इतिहास, जिससे जोखिम बढ़ जाता है। सरकारी गारंटी भी केवल आंशिक नुकसान कवर करती है। ऐसे में शेयरधारकों से संचालित संस्थानों के लिए यह काम आकर्षक नहीं है। इसके उलट सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक लगभग पूरा बोझ उठाते हैं-चाहे जन धन, मुद्रा या विश्वकर्मा जैसी योजनाएं हों, लेकिन सीमित स्टाफ और सख्त नियामक बोझ के कारण उनकी क्षमता सीमित है। जब कर्ज अटकता है तो जनता के सामने दोष बैंक या सरकार, दोनों को झेलना पड़ता है।

अनुरोध ललित जैन

> जब निजी बैंक पीछे हट रहे हों और सार्वजनिक बैंक थक चुके हों तो समाधान सहकारिता ढांचे में है

सहकारिता कुंभ का शुभारंभ करते अमित शाह ● एएनआइ

जब निजी बैंक पीछे हट रहे हों और सार्वजनिक बैंक थक चुके हों, तो समाधान सहकारिता ढांचे में है। यह भारत की सबसे पुरानी और भरोसेमंद वित्तीय व्यवस्था है। सहकारी ऋण समितियां और जिला सहकारी बैंक 'सामाजिक गारंटी' पर काम करते हैं, जहां हर सदस्य की गारंटी दूसरा सदस्य देता है। यह सामुदायिक भरोसा उन कारीगरों के लिए अधिक उपयोगी है, जिनके पास औपचारिक रिकार्ड नहीं है। इन संस्थाओं में डिफाल्ट दर औसतन दो प्रतिशत के आसपास रहती है, जो अधिकांश सूक्ष्म ऋणों से बेहतर है। कई राज्यों में सहकारी संस्थाएं डेरी, हैंडलूम और ग्रामीण उद्यमों में गहराई से जुड़ी हैं। उन्हें स्थानीय व्यापार और मौसमी आय का अनुभव है। एक कुम्हार या बढ़ई भले फिनटेक न समझे, सहकारी संस्था को समझता है। यदि विश्वकर्मा योजना को इन सहकारी नेटवर्क से जोड़ा जाए तो यह योजना वास्तव में जन-संचालित बन सकती है, जैसे उत्तर प्रदेश के बुनकर समाज या गुजरात की डेरी सहकारिताओं में हुआ है।

सरकार को चाहिए कि सहकारी और जिला केंद्रीय बैंकों को निर्धारित बैंकों की तुलना में बेहतर ऋण गारंटी दे, क्योंकि इनका सामाजिक आधार अधिक गहरा है। नाबार्ड या सिडबी के माध्यम से कारीगर ऋणों के लिए पुनर्वित्त सुविधा खोली जा सकती है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटलीकरण 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है। इन्हें भी सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए। जो सहकारिताएं ऋण वितरण और वसूली में अच्छा प्रदर्शन करें, उन्हें ब्याज सब्सिडी या प्रशासनिक सहायता दी जा सकती है। सरकार एनईएफटी/आरटीजीएस शुल्क, केवाईसी सत्यापन और क्रेडिट ब्यूरो फीस जैसी छोटी, पर बार-बार आने वाली लागतें भी सहकारिताओं के लिए माफ कर सकती है। एक विशेष कोष बनाकर उन सहकारिताओं के प्रशासनिक खर्च का कुछ हिस्सा वापस किया जा सकता है, जो वित्तीय समावेशन के लक्ष्य पूरे करती हैं। यह सच है कि कई सहकारी संस्थाएं पूंजी की कमी, कमजोर प्रबंधन या डिजिटलीकरण की कमी से जूझ रही हैं, पर इन्हें सुधारा जा सकता है। पारदर्शी आडिट, पदाधिकारियों का रोटेशन एवं सरकार से कार्यशील पूंजी सहयोग जैसी पहलें भरोसा बहाल कर सकती हैं। प्रशिक्षण शिविर सहकारिता प्रबंधन में ईमानदारी और दक्षता बढ़ाएंगे। असली वित्तीय समावेश तभी होगा हम जब उन संस्थाओं को मजबूत करें, जो अपने लोगों को जानती हैं, क्योंकि क्रेडिट केवल पूंजी नहीं, भरोसा भी है।

(लेखक आल इंडिया कांग्रेस माइनारिटी सेल के उपाध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

आतंक का चेहरा

आतंकवाद वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए साजिशों के नए-नए जाल बुनते हैं, जिन्हें भेद पाने में सुरक्षा एजंसियों को भी कड़ी चुनौतियां का सामना करना पड़ता है। सुरक्षा एजंसियों को इसी तरह के एक अंतरराज्यीय आतंकी संजाल का भंडाफोड़ करने में सफलता मिली है, जिसमें आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस साजिश की भयावहता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि आरोपियों के ठिकानों से 2,900 किलोग्राम विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए हैं। यानी वे किसी बड़े खौफनाक हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस का दावा है कि आतंकियों का यह तंत्र पाकिस्तान की धरती से संचालित होने वाले जैश-ए-मोहम्मद और आइएसआइएस से संबंधित अंसार गजवातुल-हिंद से जुड़ा हुआ था, जो जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सक्रिय था। सवाल है कि इस गिरोह से जुड़े लोग इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक पदार्थ और हथियार जमा करने में कैसे कामयाब हो गए? सुरक्षा और खुफिया एजंसियों को इनकी गतिविधियों की भनक पहले क्यों नहीं लग पाई?

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पुलिस तथा केंद्रीय एजंसियों के साथ विशेष अभियान चलाकर इस आतंकी तंत्र का पर्दाफाश किया है। खास बात यह है कि इस गिरोह के जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनमें एक विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक और एक चिकित्सक भी शामिल हैं। साफ है कि आतंकी संगठन पढ़े-लिखे लोगों को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं, ताकि किसी हिंसक वारदात को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया जा सके। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों में से एक के दिल्ली से सटे फरीदाबाद स्थित किराए के मकान से 360 किलोग्राम ज्वलनशील पदार्थ बरामद किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में इतने बड़े पैमाने पर ज्वलनशील पदार्थ का मिलना कई सवाल खड़े करता है। एनसीआर में जगह-जगह पुलिस की ओर से सुरक्षा नाके लगाए गए हैं, इसके बावजूद विस्फोटक पदार्थ की इतनी बड़ी खेप आखिर वहां कैसे पहुंचाई गई? क्या खुफिया और सुरक्षा एजंसियों की जांच का व्यवस्थागत तंत्र इतना कमजोर है कि वह वास्तविक समय पर आपराधिक गतिविधियों को पकड़ पाने में सक्षम नहीं है?

गिरफ्तार किए गए आठ लोगों में से सात कश्मीर के हैं, जबकि एक उत्तर प्रदेश का निवासी है। सुरक्षा अधिकारियों का दावा है कि जांच में दो आरोपियों के मोबाइल फोन में पाकिस्तान के कई नंबर पाए गए हैं। जाहिर है कि वे पाकिस्तान में अपने आकाओं के संपर्क में थे। यह सवाल भी महत्त्वपूर्ण है कि गिरफ्तार सभी आरोपी स्थानीय हैं, मगर उनके पास चीनी स्टार पिस्तौल, एके-56 एवं एके क्रिंकाव राइफल जैसे हथियार और इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक पदार्थ कहां से आए? प्रारंभिक जांच में यह बात भी सामने आई है कि धन का लेन देन करने और साजो-सामान की व्यवस्था के लिए यह गिरोह गुप्त माध्यमों का इस्तेमाल कर रहा था। सामाजिक और धर्मार्थ कार्यों की आड़ में पेशेवर तथा शैक्षणिक तंत्र के जरिए धन जुटाया जाता था। मगर ऐसा कैसे संभव हुआ कि खुफिया और सुरक्षा एजंसियों को इसकी पहले कोई भनक नहीं लग पाई। जाहिर है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कहीं न खामियां व्याप्त हैं, जिन्हें दुरुस्त किए जाने की जरूरत है।

हादसों की जड़ें

लगभग सभी बड़े हादसों और उनमें लोगों के हताहत होने की घटना के बाद राहत तथा मुआवजे के लिए सरकार की ओर से औपचारिक कदम उठाए जाते हैं। सबका ध्यान आमतौर पर इस बात पर टिका रहता है कि किस वाहन के चालक की गलती थी या कहीं कोई तकनीकी गड़बड़ी तो नहीं थी। मगर कई बार हादसों की वजहें ऐसे पहलू में भी छिपी होती हैं, जिन पर ध्यान देना लोग जरूरी नहीं समझते और न ही उसे अहम बिंदु माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए कुछ वैसे ही कारणों को चिह्नित करने की जरूरी पहल की है। अदालत ने सोमवार को राजस्थान के फलोदी इलाके में हुए सड़क हादसे के मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से दो हफ्तों के भीतर दुर्घटना के कारणों पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इसमें संबंधित महकमों को फलोदी से गुजरने वाले राजमार्ग पर ढाबों की संख्या के साथ-साथ राजमार्ग की स्थिति और वहां सड़क रखरखाव के लिए ठेकेदार द्वारा अपनाए गए मानदंडों के बारे में भी बताना होगा।

गौरतलब है कि उस हादसे में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक के पीछे यात्रियों से भरा टेम्पो ट्रेवलर टकरा गया था, जिसमें दस महिलाओं और चार बच्चों सहित पंद्रह की जान चली गई थी। दरअसल, लंबी दूरी की यात्रा के लिए निर्बाध सड़कें तो बना दी जाती हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता और रखरखाव के लिए उच्चतम मानदंडों को बनाए रखना जरूरी नहीं समझा जाता। जबकि हर कुछ दूरी पर टोल संग्रह केंद्रों पर वाहन चालकों से शुल्क वसूलने में कोई रियायत नहीं बरती जाती। दूसरी ओर, ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, जिनमें किसी ढाबे के पास सड़क किनारे खड़े बड़े वाहन पर सही समय पर नजर न पड़ने की वजह से पीछे से कोई अन्य वाहन आकर टकरा जाता है और नाहक ही लोगों की जान चली जाती है। सवाल है कि जब तेज रफ्तार और निर्बाध सफर के लिए सड़कें बनाने का दावा किया जा रहा है, तो उसे हर लिहाज से सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी किसकी है। सुप्रीम कोर्ट ने फलोदी में हुए हादसे का स्वतः संज्ञान लेकर दरअसल हादसों के वास्तविक कारणों की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश की है।

समाज में वैचारिक क्रांति की दरकार

वर्तमान में सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर समस्याएं और चिंता बनी हुई हैं। इनका समाधान निकालना केवल सरकार का नहीं, बल्कि समाज का भी कर्तव्य है। इसमें धर्मगुरुओं तथा बौद्धिक वर्ग की भूमिका अहम हो सकती है।

जगमोहन सिंह राजपूत

लोकतंत्र में चुनाव जब केवल सत्ता पाने के लिए रणनीति बनाने तक सीमित हो जाएं, तब देश के प्रबुद्ध वर्ग का कर्तव्य और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है। भाषण चाहे राजनीति से जुड़ा हो या फिर किसी अन्य विषय से, उसमें समस्या और समाधान दोनों हों, तभी वह सार्थक कहलाता है। स्वामी विवेकानंद ने जब शिकागो में 11 सितंबर 1893 को अपने ऐतिहासिक भाषण में अमेरिका के लोगों को 'बहनों एवं भाइयों' कहकर संबोधित किया, तो वहां मौजूद भीड़ इन शब्दों को सुनकर आह्लादित हो उठी। वे सनातन धर्म के प्रतिनिधि थे, जिसमें हर पंथ ससम्मान और समकक्ष स्वीकार्य था। ऐसा कोई बंधन नहीं था कि अमुक पूजा पद्धति को ही अपनाएं, या किसी एक धार्मिक पुस्तक को पूरी तरह स्वीकार करें। यह सभ्यता और सनातन ज्ञान परंपरा हर प्रकार की जकड़न से मुक्त थी। आप पूजा करें या न करें, ईश्वर को मानें या न मानें, जब तक आप समाज की मर्यादाओं को स्वीकार करते हैं, आप हिंदू हैं। ऐसा कोई बंधन नही था कि आपका आस्तिक होना आवश्यक है!

स्वामी विवेकानंद ने सनातन संस्कृति की विश्व-व्यापकता को जिस ढंग से प्रस्तुत किया, वह अद्वितीय था। यह भी ऐतिहासिक तथ्य है कि जब अब्राहमी धर्म के लोग यहां आए, तो भारत के लोगों ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने धर्म के अनुसार परंपराओं एवं मान्यताओं को आगे बढ़ाने का हर एक अवसर दिया। पारसी मत को मानने वालों का यहां आना इसलिए ज्यादा महत्त्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वे यहां आकर पूरी तरह घुलमिल गए। आज उनकी संख्या कम होने के बावजूद उन्हें सम्मान की नजर से देखा जाता है। देश के निर्माण में उन्होंने जो योगदान दिया है, वह किसी अन्य धर्म से कम नहीं है। भारत में इस समय सभी बड़े पंथों के अनुयायी रहते हैं और उन सभी ने यहां की सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया है।

इस समय देश में सांप्रदायिक माहौल को लेकर विचार अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन यह स्पष्ट है की यदि आजादी के बाद यानी भारत विभाजन के पश्चात के समय पर दृष्टि डाली जाए, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि वर्तमान में धार्मिक ढांचे और सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर समस्याएं और चिंता बनी हुई हैं। इनका समाधान निकालना केवल सरकार का नहीं, बल्कि समाज का भी कर्तव्य है। इसमें धर्मगुरुओं तथा बौद्धिक वर्ग की भूमिका अहम हो सकती है। इस कर्तव्य को पहचानना और उसे अंगीकार कर समाधान में लगना हर भारतीय का उत्तरदायित्व है। इस कार्य को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

यह सवाल भी अहम है कि क्यों सामुदायिक मनमुटाव का लाभ उठाने के लिए अनेक राजनीतिक दल अपने-अपने ढंग से अग्रसर हो गए हैं। वे दलगत हित और चुनाव जीतने जैसे सामान्य लक्ष्य को राष्ट्रहित के ऊपर प्राथमिकता देने में नहीं हिचक रहे हैं। इस क्रम में समाज में जातिगत भेदभाव बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। किसी भी सामान्य नागरिक को यह लगता है कि जिस जाति प्रथा को समाप्त करने में महात्मा गांधी और बाबा साहब आंबेडकर जैसे अनेक मनीषियों ने जीवन लगा दिया,

उन्हीं के नाम पर राजनीति करने वाले आज पूरे प्राणप्रण से जाति प्रथा के आधार पर देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रहित पर इसका दीर्घकालिक और नकारात्मक असर पड़ता है, इसलिए सांप्रदायिक और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए सभी की भागीदारी आवश्यक

> कुछ रूढ़िवादी विचार समय के साथ इतने सशक्त हो जाते हैं कि उनसे पार पाने में सदियां लग जाती हैं। लंबे संघर्ष के पश्चात भारत के संविधान में जाति प्रथा और छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, फिर भी यह सब समाप्त नहीं हुआ है। देश के युवाओं को इस ओर विशेष ध्यान देना होगा कि छोटे-छोटे राजनीतिक लक्ष्य सामने रखकर दलगत लाभ लेने के लिए समाज को सांप्रदायिक और जातिवाद के आधार पर विभाजित करने वालों से सावधान रहें। देश की भावी पीढ़ी को खुद को इस सबसे बचाना होगा और सामाजिक सद्भाव बढ़ाने की चुनौती को स्वीकार करना होगा।

है। समाज में एक आंतरिक वैचारिक क्रांति लानी ही होगी और ऐसा तभी संभव होगा, जब हर तरुण, युवा और बुद्धिजीवी इस विचार में रच-बस जाएं कि देश तभी समृद्ध होगा, जब यहां अटूट भाईचारा और पंथिक सद्भाव सारे विश्व को दिखाई देगा! देश तभी सुरक्षित होगा, जब अपने अनुभव से सीख कर हर भारतवासी यह अंतर्मन से स्वीकार करेगा कि देशहित सर्वोपरि है और बाकी सब कुछ इसके बाद ही आता है। इसके लिए बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक तैयारी आवश्यक है।

यह सब कैसे संभव होगा, इसकी सीख स्वामी विवेकानंद हमें बहुत पहले यह कह कर दे गए थे कि बड़े काम में बहुत समय तक लगातार और महान प्रयत्न की आवश्यकता होती है। यदि ऐसे कार्य में कुछ लोग विफल भी हो जाएं, तो भी उसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। संसार का यह नियम है कि अनेक लोग नीचे गिरते हैं और उनमें से कुछ फिर उठ खड़े हो जाते हैं। कितने ही दुख आते हैं, कितनी ही भयंकर कठिनाइयां सामने उपस्थित होती हैं। स्वार्थ और अन्य बुराइयों का मानव-हृदय में घोर संघर्ष होता है और तभी आध्यात्मिकता की अग्नि से इन सबका विनाश होने लगता है। इस जगत में भलाई का मार्ग सबसे दुर्गम एवं पथरीला है। कितने लोग सफलता प्राप्त करते हैं और कितने विफल हो जाते हैं, इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हजारों ठोकरें खाने के बाद चरित्र का निर्माण होता है।

कुछ रूढ़िवादी विचार समय के साथ इतने सशक्त हो जाते हैं कि उनसे पार पाने में सदियां लग जाती हैं। लंबे संघर्ष के बाद भारत के संविधान में जाति प्रथा और छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया, फिर भी यह सब समाप्त नहीं हुआ है। देश के युवाओं को इस ओर विशेष ध्यान देना होगा कि छोटे-छोटे राजनीतिक लक्ष्य सामने रखकर दलगत लाभ लेने के लिए समाज को सांप्रदायिक और जातिवाद के आधार पर विभाजित करने वालों से सावधान रहें। देश की भावी पीढ़ी को खुद को इस सबसे बचाना होगा और सामाजिक सद्भाव बढ़ाने की चुनौती को स्वीकार करना होगा। इस संसार में प्रकृति ने जो सृजन किए हैं, उसमें विविधता की सुंदरता को समझने के लिए वह सदा प्रेरित करती है। पंथिक विविधता को भी उसमें निहित सुंदरता को ध्यान में रखकर समझना होगा। ऐसा कौन-सा धर्म या पंथ है, जो सत्य, शांति, अहिंसा, प्रेम और सदाचार की बात नहीं करता या उसका समर्थन नहीं करता है? जरूरत है तो इन तत्त्वों को अपने जीवन में आत्मसात करने और उनके अनुरूप आचरण की।

स्वामी विवेकानंद ने मानव जीवन को रास्ता दिखाया था। उन्होंने यहां तक कहा था कि पूजाघर में जाना तब प्राथमिकता में नहीं है, अगर उसी समय किसी अकिंचन व्यक्ति को आपकी सेवा की आवश्यकता हो। दीन-दुखियों की सेवा ईश्वर की सेवा से कम नहीं है। उन्होंने यह सीख भी दी थी कि यदि आप मानते हैं कि हर मनुष्य में ईश्वर विद्यमान है, तो फिर हमारे पास दूसरे की सहायता करने का अधिकार रह ही नहीं जाता है, हम केवल सेवा ही कर सकते हैं।

जहां तक समस्याओं के समाधान के कौशल की बात है तो शिक्षण संस्थाओं से इसकी शुरुआत की जा सकती है। राष्ट्र और मानव प्रेम की भावनाओं के साथ यदि व्यक्तित्व विकास होगा, तो निश्चित रूप से देश में सामाजिक सद्भाव और पंथिक समरसता के साथ-साथ सेवा भावना बढ़ेगी। इसी से भविष्य में देश की प्रगति और विकास को गति मिलेगी तथा भारत विश्व में अपना अपेक्षित स्थान प्राप्त कर सकेगा।

सफलता के शिखर पर पहुंचती लड़कियां

डॉ कविता विकास
लेखिका
kavitavikas28@gmail.com

रात के अंतिम पहर के एक सिरे को पकड़, अधखुली आंखों को धीरे-धीरे खोलती हुई, कुछ क्षण वह आस-पास की शांति को जीती है, फिर पूरी तरह सुरक्षित महसूस करते ही आंखें खोल देती है. छोड़ देती है रात का सिरा और पूरे विश्वास के साथ अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है. भोर का सुबह बनना, यानी एक बालिका का आत्मनिर्भर लड़की बनना. हमें कामना करनी चाहिए कि हर लड़की के जीवन का सूर्य चमकता रहे, वह उसके साथ दूसरों को भी उजाले के सुख से परिचय करवाता रहे.

एक मुकाम पर पहुंच कर अनेक को प्रेरित करने वाली लड़कियां हमें अपने परिवेश में खूब दिख जायेंगी. समाचारों की सुर्खियां बनने वाली ये लड़कियां अपनी मेहनत और संघर्ष का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करती हैं. किसी भी क्षेत्र को उठा कर देख लीजिए, लड़कियों ने सफलता का परचम लहराया हुआ है. पर स्टार से स्टारडम तक का सफर जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है वहां लंबे समय तक बने रहना. शहरी क्षेत्रों में तो काम के बहुत सारे आयाम होते हैं, पर छोटी जगहों से आने वाली लड़कियां खेल और पढ़ाई दोनों में अव्वल आकर, मेडल लाकर, देश का मान बढ़ा और समाचार पत्र की हेडलाइंस बन कर भी कहां गुम हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता. यदा-कदा किसी सार्वजनिक समारोह में दिख गयीं इन बेटियों से बात करके जो निष्कर्ष सामने आया, वह यह है कि आर्थिक विपन्नता इन्हें परिवार चलाने के लिए कामों में उलझा देती है. सरकारी सुविधाओं की प्रक्रिया में देर लगती है, तब तक भी तो अपने भरण-पोषण के लिए सोचना है. मैंने स्वयं अनेक महिला हॉकी खिलाड़ियों को धान बुवाई के समय खेतों में काम करते देखा है, जीविकोपार्जन का कोई अन्य स्रोत नहीं है उनके पास.

बुलंदियों पर भला किसका समय ठहरा है. इस ऊंचाई से नीचे धकेलने वालों की भी कमी नहीं है. इसलिए, इस पद का सम्मान करना भी सीखना होगा. महिलाओं के लिए विशेषकर ऐसे पद के सम्मान को संजोये रखना जरूरी है, क्योंकि महिलाओं को उच्च पद पर आसीन देखने की आदत भी लोगों को कम ही है. इसलिए किसी अच्छे पद पर रहते हुए स्त्री-पुरुष दोनों को अधिक से अधिक सामाजिक हित के लिए काम करना चाहिए. दूसरों के लिए जी कर देखिए, जो नाम और मान मिलता है, वह किसी अन्य काम में नहीं. अपने आसपास ही नजर दौड़ाएं, तो ऐसे अनेक लोग मिल जायेंगे जो सफलता के शिखर पर पहुंच कर भी साधारण-सी जिंदगी जी रहे हैं, जबकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है. संतुष्टि पैसे से नहीं, काम से आती है. सो, इसे ही अपना ध्येय बनाना चाहिए.

Prabhat khabar Page No-8

कॉप-30 की शुरुआत

तीसवें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की शुरुआत ब्राजील में हो गयी. यह वार्षिक शिखर सम्मेलन उन देशों को एक मंच पर लाता है, जिन्होंने 1992 की संयुक्त राष्ट्र जलवायु संधि पर दस्तखत किये थे. इस संधि का उद्देश्य सभी देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रतिबद्ध करना है. सम्मेलन ऐसे समय शुरू हुआ है, जब वैश्विक तापमान ने नये रिकॉर्ड बनाये हैं और जलवायु परिवर्तन की भीषणता का अनुभव पूरी दुनिया कर रही है. पिछले कुछ वर्षों से यह सम्मेलन भू-राजनीतिक और वित्तीय चर्चा का मंच बन गया है. इसके बावजूद इस सम्मेलन का महत्व है. दरअसल बत्तीस साल पहले ब्राजील में ही जलवायु संधि पर दस्तखत किये गये थे. ऐसे में, इस सम्मेलन को अपनी जड़ों की ओर लौटना कहा जा रहा है. यह अकारण नहीं है कि ब्राजील ने इस सम्मेलन के लिए उस बेलेम शहर को चुना, जो अमेजन क्षेत्र में स्थित दुनिया का सबसे विशाल उष्णकटिबंधीय वर्षावन है. इस विशाल वनक्षेत्र में वातावरण से कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता है और यह वनों की कटाई तथा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर है. ब्राजील चाहता है कि सम्मेलन में बड़े-बड़े वादे करने के बजाय सदस्य देश पिछले वादों को पूरा करने पर ध्यान दें. जैसे कि कॉप-28 में जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का वादा किया गया था. भारत इस सम्मेलन में अपनी स्वच्छ ऊर्जा नीति पर प्रकाश डालेगा. गौरतलब है कि भारत ने निर्धारित समय से पहले ही 50 प्रतिशत गैर जीवाश्म ऊर्जा का लक्ष्य हासिल कर लिया है. लेकिन वैश्विक स्तर पर उस दिशा में अभी बहुत काम करना है. आगामी 21 नवंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में जलवायु वित्त और तापमान वृद्धि जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी. तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखे जाने का संकल्प यहां भी दोहराया जायेगा, हालांकि अब यह लक्ष्य कठिन जान पड़ता है. जहां तक जलवायु वित्त की बात है, तो पिछले सम्मेलन में 2035 तक विकसित देशों द्वारा 300 अरब डॉलर विकासशील देशों को दिये जाने का मुद्दा प्रमुख था. इस बार इसे अंतिम रूप दिये जाने की बात है. लेकिन अमेरिका के पीछे हटने से इस पर असर पड़ेगा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भी इसमें भाग लेने की संभावना नहीं है. विकसित देशों के उदासीन रवैये से स्थिति इतनी बिगड़ गयी है कि वार्ता से आगे बढ़ कर अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है.

ब्राजील में शुरू हुए कॉप-30 में तापमान वृद्धि और जलवायु वित्त जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी. दरअसल विकसित देशों के उदासीन रवैये से स्थिति इतनी बिगड़ गयी है कि वार्ता से आगे बढ़ कर अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है.

Prabhat khabar Page No-8

महिलाओं की शिक्षा को जरूरी मानते थे मौलाना आजाद

कृष्ण प्रताप सिंह
वरिष्ठ पत्रकार
kp_faizabad@yahoo.com

जयंती विशेष

वह आजाद देश के पहले शिक्षामंत्री बने, तो यूजीसी, आइआइटी और संगीत नाटक, साहित्य व ललित कला जैसी अकादमियों की स्थापना की पहल की. नैतिक वह इतने थे कि मंत्री रहते हुए देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' लेने से मना कर दिया था.

मौलाना अबुल कलाम आजाद मुस्लिम लीग के नेता मुहम्मद अली जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत और भारत के विभाजन के मंसूबे के इतने प्रबल विरोधी थे कि उनको नाकाम करने के लिए कुछ और समय तक अंग्रेजों की गुलामी करने को तैयार थे. वह भी तब, जब उनका मानना था कि गुलामी दुनिया की सबसे बुरी शय है. विडंबना यह कि ऐसे दृढ़ रुख के बावजूद वह देश को विभाजन की विभीषिका से बचा नहीं पाये. बाद में वह आजाद देश के पहले शिक्षा मंत्री बने, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और संगीत नाटक, साहित्य व ललित कला जैसी अकादमियों की स्थापना की पहल की.

नैतिक वह इतने थे कि मंत्री रहते हुए देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' लेने से मना कर दिया था. इसके अलावा, वह इस्लाम के अनूठे विद्वान, 'इंडिया विन्स फ्रीडम' जैसी कालजयी कृति के लेखक और कवि, पत्रकार, संपादक, क्रांतिकारी व खिलाफत आंदोलनकारी के रूप में भी जाने जाते हैं. महात्मा गांधी के अप्रतिम अनुयायी, सत्याग्रही, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के सबसे कम उम्र अध्यक्ष के रूप में भी उनकी पहचान रही. इसके अलावा भी उनके व्यक्तित्व व कृतित्व के कई आयाम थे. जैसे कि उनकी दृढ़ता कमजोर क्षणों में और प्रबल हो जाती थी. विभाजन के जिन्ना के मंसूबे के विरुद्ध तो उन्होंने इस दृढ़ता का प्रदर्शन किया ही, इसका एक उदाहरण 1945 में तब भी पेश किया, जब भले ही देश आजादी की आहट महसूस करने लगा था, पर गोरी सरकार को उन्हें जेल से छोड़ना गवारा नहीं था. उसी दौरान कलकत्ता में उनकी पत्नी का निधन हो गया, तो कई हलकों

मौलाना अबुल कलाम आजाद
(11 नवंबर, 1888-22 फरवरी, 1958)

से सुझाव आये कि वह सरकार से पैरोल पर रिहाई मांग लें. पर उन्होंने यह कहकर सारे सुझाव ठुकरा दिये कि ऐसा करना आजादी देने में टालमटोल करती आ रही अन्यायी अंग्रेज सरकार से दया की याचना करने जैसा होगा.

अनंतर, उन्होंने इस याचना के बजाय अपने धैर्य को असीम कर लिया और पत्नी के बिछोह का सारा दुख अंदर ही अंदर सह गये. उनके अनुयायियों ने उनकी पत्नी का स्मारक बनाने के मकसद से धन जुटाने के लिए बेगम आजाद स्मृतिकोष बनाया, तो देश के लोगों ने उसके लिए इतने खुले हाथों दान दिया कि मौलाना के जेल से बाहर आने तक कोष में बड़ी रकम जमा हो गयी. अनुयायियों ने सोचा था कि मौलाना इस बाबत जानेंगे तो बहुत खुश होंगे. लेकिन मौलाना इतने नाराज हुए कि फौरन धन संग्रह रोक देने को कह दिया. साथ ही, कोष में जमा हुई सारी धनराशि इलाहाबाद के कमला नेहरू अस्पताल को देने का 'आदेश' दे डाला. अनुयायी इसके प्रति अन्यमनस्क दिखे, तो उनसे साफ कह दिया कि देशवासियों से एकत्र किया गया कोई भी धन किसी व्यक्ति के नहीं, लोक के हित में ही खर्च किया जाना चाहिए. महात्मा गांधी की ही तरह वह किसी को सिर्फ जुबानी जमा-खर्च से कुछ सिखाने की कोशिशें करने के विरुद्ध थे. वह खुद को ईश्वर की संतान और 'अपने साथ घटित होने वाली हर चीज से महान' बताते और कहते थे कि मैं उस अविभाज्य एकता का हिस्सा हूं, जो भारतीय राष्ट्रीयता है. शिक्षाविद के तौर पर उनका कहना था कि शीर्ष पर चढ़ने के लिए ताकत की आवश्यकता होती है. शिक्षकों से उनकी अपेक्षा थी कि वे छात्रों में जिज्ञासा, रचनात्मकता, उद्यमशीलता और नैतिक नेतृत्व की भावना का विकास करें और उनके आदर्श बनें.

कला और संगीत को वह भावनाओं की शिक्षा मानते थे और कहते थे कि ये सच्ची राष्ट्रीय शिक्षा की किसी भी योजना के अनिवार्य तत्व हैं. उनका कहना था कि शिक्षा माध्यमिक स्तर की हो या विश्वविद्यालय स्तर की, तब तक पूर्ण नहीं मानी जा सकती, जब तक वह शिक्षार्थियों की क्षमताओं को सौंदर्य बोध के लिए प्रशिक्षित न करे. उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी शिक्षा पाने का अधिकार है, जो उसे अपनी क्षमताओं का विकास करने और पूर्ण मानव जीवन जीने में सक्षम बनाये, और राष्ट्रीय शिक्षा का कोई भी कार्यक्रम तब तक उपयुक्त नहीं हो सकता, जब तक वह महिलाओं की शिक्षा और उन्नति पर पूर्ण ध्यान न दे. उनका यह भी मानना था कि जो व्यक्ति संगीत से प्रभावित नहीं होता, वह मानसिक रूप से अस्वस्थ व असंयमी तो होता ही है, आध्यात्मिकता भी से दूर होता है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

Prabhat khabar Page No-8

'त्रिशूल' के जरिये पाकिस्तान को संदेश

हर्ष कक्कड़
मेजर जनरल, (सेवानिवृत्त)
kakarharsha@gmail.com

गुजरात और राजस्थान में आयोजित त्रिशूल सैन्याभ्यास में तीनों सेना के लगभग 40,000 सैनिकों की भागीदारी है. इस लिहाज से हाल के वर्षों में यह सबसे बड़ा सैन्याभ्यास है. इस सैन्याभ्यास को जिस क्षेत्र में अंजाम दिया जा रहा है, वही पाकिस्तान के लिए ठोस संदेश है कि सीमा पर उसकी किसी भी तरह की शरारत का जबरदस्त जवाब दिया जायेगा. त्रिशूल सैन्याभ्यास की प्रतिक्रिया में पाकिस्तान में दहशत के माहौल को साफ-साफ देखा जा सकता है. उसे यह समझ में आ गया है कि भारत बहुत कम समय में उसके खिलाफ आक्रामक कार्रवाई कर उसे भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है.

गुजरात और राजस्थान में आयोजित त्रिशूल सैन्याभ्यास में तीनों सेना की भागीदारी तो है ही, यह सैन्याभास उस सर क्रीक में भी हो रहा है, जहां पाकिस्तान ने हाल ही में कुछ ज्यादा ही रुचि दिखायी. इस सैन्याभ्यास के दायरे में अरब सागर भी है. सैन्याभ्यास में न केवल नौसैनिक जहाज, युद्धक विमान, विशेष सुरक्षा बलों, नवगठित युद्धक समूहों तथा मैकेनाइज्ड बलों की उपस्थिति है, बल्कि ये तालमेल बना कर अभ्यास कर रहे हैं. इसका समापन सौराष्ट्र के तट पर होगा, जहां हमारी तीनों सेना के जवान थल, समुद्र और आकाश में अपनी कुशलता का परिचय देंगे.

एक रक्षा प्रवक्ता ने मीडिया को बताया कि 'इस सैन्याभ्यास में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, साइबर, ड्रोन और काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस, खुफिया अभ्यास और गहन निरीक्षण के साथ एयर डिफेंस कंट्रोल तथा रिपोर्टिंग जैसी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है. यह सैन्याभ्यास जमीन, समुद्र तथा आकाश में तीनों सेना की भौतिक तथा वर्चुअल, दोनों माध्यमों में सतत तैयारी को उद्देश्य में रख कर किया जा रहा है.' इसमें लगभग 40,000 सैनिकों की भागीदारी है. इस लिहाज से हाल के वर्षों में यह सबसे बड़ा सैन्याभ्यास है. सैन्याभ्यास स्थल तथा अरब सागर में नोटम (नोटिस टू एयरमैन) जारी किया गया. ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में यह सैन्याभ्यास साझा सैन्य कार्रवाई की हमारी क्षमता तथा भविष्य में जरूरत पड़ने पर जोरदार सैन्य कार्रवाई करने का ठोस संदेश देता है. इस सैन्याभ्यास में विभिन्न स्वरूपों में एक साथ किये जाने वाले छोटे-छोटे कई अभ्यास शामिल हैं, जिनका उद्देश्य मोर्चे पर अपना वर्चस्व स्थापित करना है. नॉर्दन कमांड ने हाल ही में लद्दाख में अस्त्र शक्ति अभ्यास किया है. इसका लक्ष्य सैन्य शक्ति के प्रदर्शन, स्वार्म ड्रोन के इस्तेमाल और मानवरहित हवाई निरीक्षण व्यवस्था की मजबूती के अलावा आइटीबीपी के साथ मिल कर कमांडो ऑपरेशन को अंजाम देना था. उस अभ्यास का उद्देश्य लद्दाख जैसे संवेदनशील क्षेत्र में चीन या पाकिस्तान की किसी भी करतूत का करारा जवाब देने की क्षमता को परखना था. पिछले सैन्याभ्यास के विपरीत, जिनमें आक्रामकता के साथ रक्षात्मकता का भी मिश्रण था, त्रिशूल एक ही साथ कई जगहों पर अंजाम दिया जाने वाला उच्च तीव्रता वाला आक्रामक सैन्याभास है. ऐसा लगता है कि इस सैन्याभ्यास को परमाणु संरक्षण के अधीन अंजाम दिया गया, जिसका लक्ष्य अपने काउंटर ड्रोन तथा एयर डिफेंस प्रणाली द्वारा पाकिस्तान के जवाबी हमलों को बेअसर करना है. त्रिशूल सैन्याभ्यास उस बहुप्रतीक्षित थिएटर कमांड का पूर्वाभ्यास हो सकता है, जो सैन्य ऑपरेशन में एकजुटता तथा आत्मनिर्भरता का द्योतक होगा. वायुसेना ने भी पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में नोटम जारी किया था, क्योंकि अपनी क्षमता को परखने के लिए वह वहां अभ्यास कर रही है. वायुसेना दरअसल यह भी देखना चाहती है कि संयुक्त अभियान के तहत वह एक से दूसरे क्षेत्र में अपने सैनिकों की तैनाती तेजी से करने में सक्षम है या नहीं.

थलसेना ने बीते एक दशक में क्षमता वृद्धि की दृष्टि से कई कदम उठाये हैं. इसके अंतर्गत एकीकृत रक्षा बल, रुद्र ब्रिगेड्स, भैरव बटालियन तथा अशनि ड्रोन प्लाटूंस आदि का गठन शामिल हैं. त्रिशूल सैन्याभ्यास में इन सबकी सक्रियता है. ऑपरेशन सिंदूर में नौसेना खामोश थी. लेकिन त्रिशूल सैन्याभास में वह नेतृत्वकारी भूमिका में है. इसका संदेश यह भी है कि भविष्य में भारत द्वारा शुरू किये जाने वाले किसी भी सैन्य ऑपरेशन में नौसेना की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है. त्रिशूल सैन्याभ्यास की प्रतिक्रिया में पाकिस्तान में दहशत के माहौल को साफ-साफ देखा जा सकता है. भारत के जवाब में पाकिस्तान ने भी नोटम जारी किया, जिसका मतलब अपने सैन्य बलों को अलर्ट मोड पर रखना है. बीते कुछ दिनों में पाकिस्तान को सर क्रीक क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ाते देखा गया. इस्लामाबाद का मानना है कि उस क्षेत्र में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है. त्रिशूल सैन्याभास को जिस क्षेत्र में अंजाम दिया जा रहा है, वही अपने आप में पाकिस्तान के लिए ठोस संदेश है कि सीमा पर उसकी किसी भी तरह की शरारत का जबरदस्त जवाब दिया जायेगा. इस सैन्याभास से पाक सेना पर दबाव इसलिए भी बना है, क्योंकि अफगानिस्तान से भिड़ंत के कारण पूर्वी सीमा पर भी इस्लामाबाद को भारी संख्या में सैन्य तैनाती करनी पड़ी है. पाकिस्तान को यह भी साफ-साफ समझ में आ गया है कि भारत बहुत कम समय में उसके खिलाफ आक्रामक कार्रवाई कर उसे न सिर्फ भारी नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि इसके लिए उसे परमाणु हमलों के इस्तेमाल की भी जरूरत नहीं है.

पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आइएसपीआर) के डीजी का कहना था कि त्रिशूल सैन्याभ्यास के दौरान भारत तटीय इलाके में झूठा फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, और पाकिस्तान को निशाना बनाने में उसका लाभ उठा सकता है. इससे स्पष्ट है कि त्रिशूल सैन्याभास ने पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है. लगातार नोटम जारी करने और नौसैनिक स्तर पर चेतावनियां जारी करने से भी उसके डर का पता चलता है. पाकिस्तान की सेना त्रिशूल सैन्याभ्यास पर बहुत गहरी नजर इसलिए भी रखे हुए है, क्योंकि उसे मालूम है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर 0.2 की शुरुआत बिल्कुल इसी तरह से करेगा. जहां तक चीन की बात है, तो अस्त्र शक्ति और त्रिशूल सैन्याभ्यासों के जरिये उसे पता चल गया है कि भारतीय सेना एक ही अभियान के अंदर जल-थल और वायुसेना के समन्वित सैन्य अभियान के साथ साइबर व इलेक्ट्रॉनिक कार्रवाई करने में भी सक्षम है. इस सैन्याभ्यास को दुनिया भी भारत की मजबूत सैन्य शक्ति के सबूत के तौर पर देख रही होगी. निःसंदेह रक्षात्मक सैन्य शक्ति का अपना महत्व है, लेकिन अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए किसी देश को अंततः अपनी आक्रामकता का ही परिचय देना होगा. विभिन्न इलाकों में सैन्य बलों की मजबूत मौजूदगी के जरिये भारतीय सेना ने जहां अपनी रक्षात्मकता का परिचय दिया है, वहीं त्रिशूल जैसे सैन्याभ्यास बताते हैं कि भारत अपनी सैन्य आक्रामकता का प्रदर्शन शत्रु देश की सीमा पर और उससे आगे जाकर भी कर सकता है. त्रिशूल सैन्याभ्यास की सफलता से तीनों सेना के बीच तालमेल और समन्वित आक्रामक क्षमता का पता चला है. चूंकि इस सैन्याभ्यास में इस्तेमाल किये गये तमाम उपकरण भारत-निर्मित थे, इससे रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारतीय तकनीक की श्रेष्ठता का भी प्रमाण मिला है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

Prabhat khabar Page No-8

दूरसंचार क्षेत्र में समान व्यवहार से जुड़ा सवाल

पिछले सप्ताह की शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को वित्त वर्ष 2016-17 तक वोडाफोन आइडिया (वीआई) के एजीआर के मद में समूची बकाया रकम की नए सिरे से मूल्यांकन करने की अनुमति दी थी। यह 27 अक्टूबर को जारी किए गए उस आदेश का संशोधन था जिसमें केवल 9,450 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग पर ध्यान केंद्रित किया गया था। बाद के 3 नवंबर के आदेश ने संकट से घिरी दूरसंचार कंपनी के लिए राहत के दायरे को कई गुना बढ़ा दिया है। यह हमें इस सवाल की ओर ले जाता है कि केंद्र सरकार, (जिसकी वीआई में 49 फीसदी हिस्सेदारी है) अब क्या करेगी।

क्या सरकार 'जनहित' में इस कंपनी का एजीआर के मद में बकाया 83,400 करोड़ रुपये माफ कर देगी? क्या सरकार वित्तीय देनदारी के बदले में वीआई में अतिरिक्त हिस्सेदारी लेगी और आदित्य बिड़ला समूह और ब्रिटेन स्थित वोडाफोन के संयुक्त उद्यम वाली दूरसंचार कंपनी में बहुलांश अंशधारक बन जाएगी? इसके अलावा, सरकार भारती एयरटेल द्वारा 38,604 करोड़ रुपये के एजीआर बकाया पर राहत मांगने की याचिका से कैसे निपटेगी? अन्य प्रमुख दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो पर कोई एजीआर बकाया नहीं है क्योंकि इसने सितंबर 2016 में अपना संचालन शुरू किया था।

अगर सरकार दूरसंचार उद्योग में एकाधिकार की स्थिति रोकने के लिए कदम उठाती है, जिसमें वीआई को उसकी संचित देनदारियों पर राहत देना शामिल है, तो एक और सवाल बिल्कुल पूछा जा सकता है। क्या सरकारी स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनियां, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) मिलकर दूरसंचार उद्योग को प्रतिस्पर्धी और दो कंपनियों के एकाधिकार से मुक्त बनाए रखने के लिए आवश्यक बैंडविड्थ उपलब्ध नहीं करा सकतीं?

सामयिक सवाल

निवेदिता मुखर्जी

30 सितंबर, 2025 तक निजी दूरसंचार कंपनियों के पास 92 फीसदी से अधिक बाजार हिस्सेदारी थी जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों के पास शेष 8 फीसदी हिस्सेदारी थी।

जहां तक दो कंपनियों के एकाधिकार की बात है तो विमानन जैसे अन्य उपभोक्ता-उन्मुख क्षेत्रों में भी लगभग ऐसी स्थिति देखी जा रही है। मगर यह किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है।

एक दूरसंचार कंपनी के उपभोक्ताओं की संख्या (वीआई के मामले में लगभग 12.77 करोड़ वायरलेस/ब्रॉडबैंड ग्राहक) को अक्सर सरकार द्वारा किसी इकाई को चालू रखने के लिए उठाए गए उपायों के मुख्य कारणों में से एक के रूप में उद्धृत किया जाता है लेकिन कुछ वर्षों से मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं के लिए नंबर पोर्टेबिलिटी का विकल्प उपलब्ध रहा है। हालांकि, इतनी बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं को एक बार में समाहित करना मुश्किल होगा।

इस बिंदु पर अगर सरकार जनहित में वीआई को राहत देती है और उसके प्रतिद्वंद्वी एयरटेल को नहीं देती है तो समान कारोबारी अवसर से जुड़े सवाल उठ सकते हैं। यहां तक कि बिना एजीआर बकाए वाली अन्य कंपनियां भी संचालन के किसी अन्य क्षेत्र में समान अवसर की मांग कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड में।

सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का मामला लंबे समय से अटका हुआ है क्योंकि स्पेक्ट्रम आवंटन (किसे कितना मिलेगा और कैसे) अभी तक तय नहीं हो पाया है। हालांकि, हम जानते हैं कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए स्पेक्ट्रम वैश्विक व्यवहार के अनुरूप नीलामी के माध्यम से नहीं बल्कि प्रशासित आवंटन तंत्र के माध्यम से दिए जाएंगे।

इस खंड में संभावित खिलाड़ियों के बीच विभाजन समान अवसर के सवाल पर फिर से उभर सकता है। पुरानी दूरसंचार कंपनियों (जो अब सैटेलाइट ब्रॉडबैंड में भी प्रवेश कर रही हैं) का तर्क यह रहा है कि उन्होंने 3जी, 4जी और 5जी सेवाओं में शामिल होने के लिए काफी पैसे खर्च किए हैं जबकि नई कंपनियां जैसे स्टारलिंक (ईलॉन मस्क द्वारा प्रचारित) या प्रोजेक्ट कुइपर (जेफ बेजोस द्वारा प्रचारित) के साथ ऐसी बात नहीं है। ये कंपनियां नए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के माध्यम से भारतीय बाजार में प्रवेश कर रही हैं। अगर मस्क और बेजोस की कंपनियां भारत में खुदरा दूरसंचार बाजार में उतरती हैं तो समान अवसर का सवाल निश्चित रूप से उठेगा।

तकनीक के क्षेत्र में ई-कॉमर्स पहले ही समान अवसर के दो पहलू देख चुका है। भारतीय ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए इन्वेंट्री-आधारित व्यवसाय की अनुमति है जबकि विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियां केवल मार्केटप्लेस मॉडल का पालन कर सकती हैं। दोनों स्वरूपों में व्यवसाय करने के नियम बहुत अलग हैं और इस अंतर का कोई विशिष्ट कारण या तर्क नहीं दिया गया है। बताया जाता है कि इन्वेंट्री बनाम मार्केटप्लेस पर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में चर्चा की जा रही है। सरकार द्वारा निर्यात के उद्देश्य से इन्वेंट्री-आधारित ऑनलाइन व्यवसाय में विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों को अनुमति देने की संभावना है।

कुल मिलाकर नियमों की एकरूपता को लेकर सभी क्षेत्रों में एक मानक होना चाहिए। अलग-अलग नियम, चाहे वे दूरसंचार कंपनियों, खुदरा संस्थाओं या ऑनलाइन व्यवसायों में हों, हमेशा समान अवसर के सवालों को जन्म देंगे।

एक विशेष दूरसंचार कंपनी को राहत देने के लिए सरकार को अनुमति देने वाले उच्चतम न्यायालय के हालिया आदेश को सभी हितधारकों द्वारा सही भावना से लिया जाना चाहिए। यह सरकार को किसी निजी दूरसंचार कंपनी की वित्तीय देनदारियों को बट्टे खाते में डालने का न्यायालय का निर्देश नहीं है। इसके बजाय यह सरकार के लिए करों और शुल्कों को युक्तिसंगत बनाने के लिए एक शुरुआती बिंदु हो सकता है ताकि दूरसंचार उद्योग भविष्य में बेहतर स्थिति में रहे।

Business Standard Page No-7

अजय मोहंती

लोकलुभावन कदमों का जाल और उसकी कीमत

भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के नीचे उप-राष्ट्रीय यानी राज्यों में राजकोषीय विचलन की गहराती दरार की अब अनदेखी नहीं की जा सकती है। बता रहे हैं अमरेंदु नंदी

बिहार के साथ ही चुनावों का एक अहम चक्र शुरू हो रहा है जो अगले दो साल तक चलेगा। इस दौरान 11 अन्य राज्यों में भी चुनाव होंगे। हमेशा की तरह चुनाव के पहले बंटने वाली 'रेवड़ी' और लोकलुभावन वादे इस दौरान सुर्खियों में रहेंगे। इससे भी ज्यादा अहम एक बात है जिस पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है और वह है राज्यों के वित्तीय अनुशासन का क्षरण।

देश की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के तहत उप राष्ट्रीय राजकोषीय विचलन अब अनदेखी करने लायक नहीं रह गया है। प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद के प्रमाण लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीते दो साल में आठ राज्यों के विधान सभा चुनावों से पहले 67,928 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं पर केंद्रित योजनाएं अब सामान्य हो चली हैं और इनकी मदद से अक्सर सत्ताधारी दल असंतोष से पार पाकर दोबारा चुनाव जीत जाते हैं। मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को चार कार्यकालों की सत्ता विरोधी लहर से निपटने में मदद की और उसके मत प्रतिशत में 7.53 फीसदी का इजाफा हुआ। झारखंड में मैया सम्मान योजना भी झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के लिए उतनी ही कामयाब साबित हुई। पीआरएस की एक रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि वर्ष 2024-25 में नौ राज्यों ने करीब एक लाख करोड़ रुपये की राशि महिलाओं को बिना शर्त नकदी हस्तांतरण के लिए आवंटित की। यह चुनावों से जुड़ा असाधारण राजकोषीय आवंटन था।

यह दलील दी जा सकती है कि इन वादों ने कल्याण और राजनीतिक संरक्षण के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया है। इससे राज्यों की वित्तीय व्यवस्था में लोकलुभावनवाद गहराई से शामिल हो गया। विकास अर्थशास्त्र भी बेहतर डिजाइन वाले सशर्त हस्तांतरणों का समर्थन करता है खासतौर पर महिलाओं के लिए। मुद्दा नकद हस्तांतरण नहीं बल्कि उनकी वर्तमान संरचना है जो अधिकतर बिना शर्त, सार्वभौमिक और लगभग स्थायी हो गई है। यह राजकोषीय दावों को स्थायी बनाती है और राज्यों के व्यय को उत्पादक निवेश से हटाकर बारंबार दी जाने वाली रियायतों की तरफ मोड़ देती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष तथा राज्यों के बीच लोकलुभावनवाद की होड़ का यह चक्र राजकोषीय अपव्यय का आधार बढ़ाता रहता है।

नीति आयोग के राजस्व सेहत सूचकांक (एफएचआई) 2025 जिसने 18 बड़े राज्यों का राजकोषीय मानकों पर आकलन किया, वह इस मामले में एक अच्छी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। संयुक्त ऋण-जीएसडीपी (राज्य का सकल घरेलू उत्पाद) अनुपात एक दशक पहले के 22 फीसदी से बढ़कर करीब 30 फीसदी हो गया है। ब्याज भुगतान का बोझ बढ़कर राजस्व प्राप्तियों के 21 फीसदी तक हो चुका है। पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल और राजस्थान में ऋण अनुपात बढ़कर 38 से 46 फीसदी तक जा पहुंचा है। कई राज्यों में राजस्व प्राप्ति का आधा से ज्यादा हिस्सा तो ब्याज भुगतान में चला जाता है जिसकी वजह से निवेश के लिए गुंजाइश कम रह जाती है।

फिर भी ये सुर्खियां पूरी कहानी नहीं बतातीं। बजट के बाहर की उधारी और गारंटी चुपचाप बढ़ती जा रही हैं। महाराष्ट्र की बजट से इतर गारंटियां ही लगभग 1.44 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे कई राज्य बिजली कंपनियों, सिंचाई निगमों, और परिवहन एजेंसियों के माध्यम से नियमित रूप से उधारी लेते हैं, जिससे ये दायित्व बहीखाते से बाहर रहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन तरह के दस्तूर को लेकर बार-बार चेतावनी दी है, और अनुमान लगाया है कि ऐसा छिपा हुआ कर्ज राज्यों के वास्तविक राजकोषीय घाटे में 0.5 से 1 फीसदी अंक तक की बढ़ोतरी कर सकता है। यह मौन संचय, जो अक्सर चुनावी लोकलुभावनवाद से प्रेरित होता है, राज्यों की राजकोषीय विश्वसनीयता को कमजोर करता है और स्थायी, पीढ़ी-दर-पीढ़ी विकास की नींव को कमजोर करता है।

वित्तीय बाजार भी दबाव महसूस करने लगे हैं। बैंक राज्यों के बॉन्ड में मुख्य निवेशक हैं, लेकिन उन्होंने सीमित मांग दिखाई है और कई ऑक्शन में कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। बैंक अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 2.82 लाख करोड़ रुपये की उधार लेने की योजना बना रहे हैं। वहीं आपूर्ति पाइपलाइन भारी बनी हुई है जबकि मांग कम है और रुझानों में सतर्कता है। सितंबर के आरंभ में, 10-वर्षीय राज्य विकास ऋण (एसडीएल) और केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के बीच का अंतर बढ़कर 80–100 आधार अंक तक पहुंच गया जो पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक था। हालांकि कुल यील्ड बढ़ी है, लेकिन बाजार अब भी अच्छे और कमजोर उधारकर्ताओं में फर्क करने में जूझ रहा है। पंजाब और पश्चिम बंगाल, जिनका कर्ज क्रमशः जीएसडीपी के 47 फीसदी और 39 फीसदी से अधिक है, अब भी गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राजकोषीय रूप से मजबूत राज्यों (जहां यह अनुपात लगभग 19 फीसदी है) की तुलना में थोड़े ही अधिक दरों पर धन जुटा रहे हैं। समान नीलामी प्रारूप और रिजर्व बैंक की हस्तक्षेप नीति ने इस अंतर को कृत्रिम रूप से कम कर दिया है, जबकि बैंकों की निवेश सीमा ने वास्तविक मूल्य निर्धारण की गुंजाइश को सीमित कर दिया है। ऐसे माहौल में, राजकोषी
को कोई इनाम नहीं मि
अव्यवस्था को कोई सजा
राज्यों के लिए सही रास्ते प
प्रेरणा कमजोर पड़ जाती है।

राज्यों की राजकोषीय वि
बहाल करना केवल वित्ती
संभव नहीं होगा। इसके लिए ऐ
और तंत्रों की आवश्यकत
आसान वादों की राजनीति का
सकें। केंद्र सरकार को 'नो
संबंधी नियम के प्रति
प्रतिबद्धता दिखानी होगी।
संशोधित ऋण सीमा का उ
उनके विवेकाधीन अनुदा
कटौती होना चाहिए। रा
राजकोषीय उत्तरदायित्व क
सिरे से डिजाइन करना होगा।
आधार पर जो ऋण स्थायित्व
केंद्रित हो, और जिसमें स
दायित्वों, विकास अनुमानों,
की प्रवृत्तियों को शामिल किय
यह केवल सरल घाटा
आधारित हो, जो अक्सर
लेखांकन को बढ़ावा देते हैं।

बाजारों को भी अनुशासन
निभानी होगी। राज्य विका
नीलामी में पारदर्शी जा
वास्तविक मूल्य निर्धारण तंत्र
ताकि निवेशक जोखिम की
सकें न कि उसे सब्सिडी देने
पंद्रहवें वित्त आयोग के श
उधारी ढांचे को और मजबूत
चाहिए, और उन राज्यों के लि
निर्धारित किए जाने चाहिए
राजस्व घाटा बनाए रखते हु
हस्तांतरण योजनाओं का विस

बहरहाल, अगर राजनीति
की मूल संरचना जस की तस
केवल संस्थागत सुधार पर्या
सच तो यह है कि प्र
लोकलुभावनवाद तब तक
जब तक मतदाता लगा
राजकोषीय अपव्यय की
अंदरूनी रूप से नहीं समझते।
लोकलुभावनवाद के साथ
पारदर्शिता और मत
विवेकशीलता जुड़ेगी, तभी भ
रियायतों की बजाय सुशासन
प्रतिस्पर्धा करेंगे।

(लेखक भारतीय प्रबंध
में अर्थशास्त्र और लोकनी
एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ये

Business Standard Page No-7